Union Budget (2025-2026)- Demands For Grants,

Ministry of Jal Shakti -contd.

SHRI ROBERT BRUCE C. (TIRUNELVELI): Hon. Chairperson, Madam, Thank you for this opportunity.

I am bringing to the attention of the Union Government one of the most pressing issues of this country, an issue which makes difference between life and death. In a land celebrated for its ancient rivers and revered traditions, the promise of clean, reliable water is enshrined as both a human right and a sacred trust. The Jal Jeevan Mission was launched in the year 2019 with an ambitious goal of providing assured tap water to all 19 crore rural households by 2024 but has failed to target.

Now, the scheme has been extended to 2028. If the people open the tap, no water is coming, only air alone is coming.

The Union Government has focussed on cleaning the river Ganga. It conveniently ignores the major rivers of India which is equally important and sacred to the people of those regions such as Cauvery and Thamirabarani.

I want to bring to your notice of the fate of one of the rivers of national importance ? Thamirabarani ? the Ganges of South India, which is the lifeline of two States ? Tamil Nadu and Kerala and has international ramifications effecting monsoon and climate change at the global level.

This river forms a part of internationally acclaimed Agasthya Malai Biosphere Reserve declared by UNESCO in the year 2016 and Agasthya Malai is named after Saptarishi sage Agasthya. In Tamil Nadu, this is the only perennial river of national importance, which originates in Tamil Nadu and drains into the Gulf of Munnar with its tributaries covering an

area of about 4,400 square kilometres. As most of its extensive catchment area lies in the Western Ghats, the river enjoys the full benefits of both the monsoon which make the river perennial.

At present, the river is subjected to a lot of pollution, threatening its very existence, which warranted two sitting judges of the Madurai Bench of the hon. High Court of Madras, hon. Justice G.R. Swaminathan and hon. Justice B. Pugalenthi, to visit various parts of the river, taking into account the enormity of the situation. This visit by the sitting judges is unprecedented in the history of our nation. I also accompanied the judges and visited all the places. I gathered information about the pollution and other issues affecting the river. There is a due of Rs. 2.63 lakh rupees? (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य कृपया कम्प्लीट कीजिए ।

SHRI ROBERT BRUCE C. : Two minutes, Madam. This is very important for my constituency. The river is considered a sacred river by all the people of southern Tamil Nadu. Across all religions, it is a unique testament to the secular nature of Tamil Nadu. Therefore, the Union Government has to take steps for the rejuvenation of the Thamirabarani river without showing any discrimination.

Madam, North India suffers from crop losses due to drought, while South India suffers from crop losses due to floods. Hence, my request to this Government is to release adequate funds for cleaning and rejuvenating the Thamirabarani river and allocate sufficient funds under the RRR Scheme for Nattur, Periyakulam, and Kaduvetti canals. The Union Government should construct a dam with a capacity of 1,523 micro feet. It should undertake a river interlinking project across the country on a mission mode on effective water management, saving millions of lives from both drought and floods across the country.

I call upon the Union Government to fulfil the aspirations of the people, particularly in the conservation of water which is becoming scarce day by day due to the effects of climate change. Thank you, Madam.

श्री अरुण भारती (जमुई): आज मैं जल शक्ति मंत्रालय के लिए मांग अनुदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ । यह मंत्रालय भारत के सतत विकास, जल सुरक्षा, और पर्यावरण संरक्षण का आधार है । हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस मंत्रालय ने जल प्रबंधन, स्वच्छता, और नदी संरक्षण को राष्ट्रीय प्रगति का मजबूत स्तंभ बनाया है ।

- नमामि गंगे मिशन हमारी माँ गंगा को पुनर्जनन देने की प्रतिवद्धता का प्रतीक है । वर्ष 2024 से 25 परियोजनाएँ पूर्ण हुई, जिसके साथ अब तक कुल 303 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं । इसके अतिरिक्त, 2,056 करोड़ रुपये की लागत से 39 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे कुल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 488 हो गई है, जिनकी लागत 39,730 करोड़ रुपये है ।
- सीवरेज आधारभूत संरचना में जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच 305 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उपचार क्षमता के सृजन या पुनर्वास के लिए 12 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई, और 750 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली 16 परियोजनाएँ पूर्ण हुई । अब तक गंगा बेसिन में 203 सीवरेज परियोजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनसे 6,255 मिलियन लीटर प्रतिदिन उपचार क्षमता और 5,249 किलोमीटर सीवर नेटवर्क का निर्माण हुआ है । यह हमारी पवित्र नदी की पारिस्थितिक सेहत को बहाल करने का एक विशाल प्रयास है ।
- 20 फरवरी 2024 को शुरू हुआ "नमामि निरंजना अभियान" हमारी समग्र सोच को दर्शाता है । यह अभियान निरंजना (फाल्गु) नदी के बारहमासी प्रवाह को सुनिश्चित करने और "निरंजना नदी पुनर्जनन मिशन" को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है । यह नदी अपनी सांस्कृतिक महत्ता के लिए जानी जाती है, और यह पहल पर्यावरण संरक्षण को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ती है ।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना नदियों को जोड़ने की पहली परियोजना है, जिसका कार्यान्वयन शुरु हुआ है । यह जल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला है के लिए वरदान साबित होगी । दिसंबर

2021 में 44,605 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर इस परियोजना में केंद्र का योगदान 39,317 करोड़ रुपये है । यह क्षेत्रीय जल असमानता को दूर करने की हमारी संकल्प शक्ति को दिखाता है ।

- विश्व बैंक की सहायता से चल रही बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना 19 राज्यों और तीन केंद्रीय एजेंसियों में 736 बाँधों के पुनर्वास को लक्षित करती है, जिससे जल संसाधनों की सुरक्षा और संस्थागत मजबूती सुनिश्चित हो रही है । वहीं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2021-26) के तहत 93,068 करोड़ रुपये के परिव्यय से 22 लाख किसानों को लाभमिलेगा । 2016-17 से 2023-24 तक 34.63 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले 25.80 लाख हेक्टेयर (74.5%) क्षमता सृजित की गई है ।
- जल जीवन मिशन, जो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ, ने ग्रामीण जल आपूर्ति में क्रांति ला दी है । 2019 में केवल 3.23 करोड़ परिवारों (17%) के पास नल कनेक्शन थे, लेकिन अब तक 12.19 करोड़ और परिवारों को जोड़ा गया है । आज 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.45 करोड़ (79.81%) के पास स्वच्छ नल जल है । इसके साथ ही, 2,180 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में से 1,580 को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला मान्यता बोर्ड से मान्यता मिली है ।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने अक्टूबर 2014 में 38.7% स्वच्छता कवरेज को 22 जनवरी 2025 तक 11.80 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण से 100% तक पहुँचाया है । यह स्वच्छता के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता है ।
- मैं कोसी नदी के जल का उपयोग और दोहन के लिए 11,500 करोड़ रुपये के आवंटन की भी सराहना करता हूँ, जिसमें मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शामिल है । यह सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, और जलविद्युत में बदलाव लाएगा ।
- मैं अपने संसदीय क्षेत्र जमुई की विशिष्ट जरूरतों को इस मंत्रालय के समक्ष रखना चाहता हूँ । मेरी तीन प्रमुख माँगे हैं ।
- गढ़ी बाँध की तलछट सफाई गढ़ी बाँध जमुई में जल का महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन वहां से जमा तलछट ने इसकी भंडारण क्षमता और दक्षता को कम कर दिया है । इससे स्थानीय किसानों को सिंचाई और भूजल पुनर्भरण में परेशानी हो रही है । मैं इसकी तलछट सफाई के लिए तत्काल बजटीय प्रावधान की माँग करता हूँ लाकि इसकी पूरी क्षमता बहाल हो सके ।

- ऊपरी किऊल जलाशय को गंगा से जोड़ने की परियोजना में तेजी ऊपरी किऊल जलाशय जमुई की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन गंगा से इसकी कनेक्टिविटी में देरी के कारण इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा । यह सूखे के जोखिम को कम करेगा और साल भर खेती को सहारा देगा । मैं मंत्रालय से इस परियोजना को प्राथमिकता देने और इसे तेज करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने का आग्रह करता हूँ ।
- बरनार जलाशय परियोजना में गति- बरनार जलाशय परियोजना जमुई के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकती है, जो हजारों हेक्टेयर में सिंचाई और भूजल स्तर को बेहतर करेगी । मैं इसके लिए तत्काल वित्तीय सहायता और प्रशासनिक गति की मांग करता हूं ।
- जल शक्ति मंत्रालय ने जल सुरक्षा और स्वच्छता की मजबूत नींव रखी है. लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है । गंगा पुनर्जनन से लेकर ग्रामीण नल कनेक्शन तक की प्रगति सराहनीय है, परंतु स्थानीय जरूरतों को भी उतने ही जोश से संबोधित करना होगा । जमुई के लिए मेरी माँगें गढ़ी बाँध सफाई, ऊपरी किऊल जलाशय को गंगा से जोड़ना, और बरनार जलाशय परियोजना केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि मंत्रालय के जल प्रबंधन और कृषि उत्थान के राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ी हैं ।
- मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इन माँगों को अनुदान आवंटन में शामिल करें, ताकि भारत के हर क्षेत्र में समान विकास सुनिश्चित हो ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I would like to express my views on the Demand for Grants of the Ministry of Jal Shakti, a ministry that plays a crucial role in ensuring access to clean drinking water and sustainable water management across the country. As a representative of the people of Palnadu, a region that has long suffered from severe water scarcity and contamination, I would like to raise the struggles and aspirations of my people and to highlight the urgent need for effective water governance.

The ground reality in Palnadu and several other districts of Andhra Pradesh is grim. The groundwater in Palnadu, Prakasam, Sri Satya Sai, and Ananthapuram is heavily contaminated with fluoride, making it

unsafe for consumption. The issue is not just limited to fluoride; the Krishna district has the highest electric conductivity (EC) rate in the country, indicating extreme water salinity. Palnadu and Prakasam are not far behind, ranking 11th and 16th respectively. Furthermore, the presence of arsenic in the groundwater of Ananthapuram, East Godavari, Guntur, Krishna, Nellore, and Prakasam districts, along with dangerously high nitrate levels in Palnadu, paints a concerning picture of the water crisis in my state.

Despite being located near the mighty Nagarjuna Sagar reservoir, Palnadu has been grappling with an acute drinking water crisis for years due to the failure of successive governments in effectively addressing this issue. For decades, villagers have walked miles to fetch water or have been forced to consume contaminated groundwater, leading to severe health problems, including fluorosis, which has left many disabled.

To address this crisis, a Rs 1,200-crore project has been initiated with joint funding from the Union and State governments to draw water from Nagarjuna Sagar and supply it to the region. I am elated to share that we have been successful in securing approvals and expediting this critical project. However, we must ensure that it is implemented in a timely and efficient manner. While schemes like the Jal Jeevan Mission (JJM) and AMRUT are making progress in providing tap connections, the depletion of groundwater and the persistence of fluoride contamination necessitate the establishment of a water grid project to guarantee sustainable access to safe drinking water.

I commend the Central Government for its enhanced focus on water security and management. The allocation of Rs 99,503 crore for the Ministry of Jal Shakti in 2025-26, a slight increase from Rs 98,714 crore

in 2024-25, reflects the government?s commitment to this crucial sector. However, given the magnitude of the water crisis in drought-prone regions, we must ensure that these funds are effectively utilized and reach the people who need them the most.

When we talk about water security in Andhra Pradesh, we cannot ignore the contributions of our leader, Shri Nara Chandrababu Naidu. His vision for the state has always included long-term solutions for water management. The Polavaram Project, often referred to as the "lifeline of Andhra Pradesh,? stands as a testament to this vision. This project, which has been delayed due to bureaucratic inefficiencies, needs immediate attention. As of November 2024, only 53.46% of the overall project has been completed, with land acquisition and rehabilitation lagging far behind. The budget for Polavaram has been increased to Rs 5,936 crore, but without timely execution, these funds will not benefit the displaced families who are still waiting for rehabilitation. I therefore, request for an expedited release of the central grant, currently capped at Rs 12,157.53 crore, to ensure the project's timely completion. I commend the Government for the successful implementation of the Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP) Phase-II and Phase-III. Covering 736 dams across 19 states with a total outlay of %10,211 crore, this initiative strengthens our water infrastructure and ensures the safety and efficiency of vital irrigation and hydroelectric projects.

Furthermore, under the visionary leadership of our state?s Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu, this ambitious project aims to transfer water from the Godavari River to the Penna River via the Krishna River, ensuring a more equitable distribution of water resources. The project envisions the construction of reservoirs at Bollapalli in Guntur district and Banakacherla in Nandyal district, which will be instrumental in diverting water to the parched lands of Rayalaseema. This initiative is

expected to provide drinking water to nearly 80 lakh people and irrigate approximately 7.5 lakh acres of farmland, transforming our region?s agricultural landscape and ensuring food security for countless families. Furthermore, the project is designed to harness 2,000 TMC of water, with a plan to divert two TMC feet of water daily for 100 days during the monsoon season, preventing wastage of surplus water. However, such a monumental initiative demands substantial financial investment. The estimated cost of the project stands at %80,112 crore, requiring the acquisition of 40,500 acres of land, including 17,000 acres of forest land. This is not a burden Andhra Pradesh can shoulder alone. I urge the Central Government to provide additional financial assistance and ensure unwavering support for this visionary project.

Under the Jal Jeevan Mission, Andhra Pradesh has been allocated Rs 16,855.67 crore, yet the state has utilized only 13% of these funds. Even in 2022-23 and 2024-25, the state did not withdraw any of the allocated funds. As of February 2025, only 73.74% of rural households in Andhra Pradesh have access to tap water, below the national average of 79.69%. With JJM now extended till 2028, we need support from the Central government to achieve 100% rural water coverage.

The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) is another vital scheme that requires immediate attention. The drastic reduction in revised estimates for 2024-25, from Rs 1,400 crore to Rs 100 crore, and a further budget cut to Rs 850 crore in 2025-26, raises concerns about the scheme?s implementation. In Andhra Pradesh, eight projects were taken up under the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), but only one has been completed. Worse still, no central assistance has been released for these projects since 2019. I also demand an expedited disbursement of funds to complete these crucial irrigation projects. Just as the Jal Jeevan Mission guarantees safe drinking water to every

household, our farmlands must receive assured irrigation. Expanding irrigated acreage will boost agricultural productivity and secure farmers? livelihoods. The Varikapudisela Lift Irrigation Scheme at Varikapudivagu is a decades-old dream of the people of Palnadu. I urge the Government to include it under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) to provide much-needed irrigation support to the region.

Additionally, Andhra Pradesh is not included in the Surface Minor Irrigation Programme under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Har Khet Ko Pani component, despite its drought-prone status. I urge the Central Government to consider Andhra Pradesh?s inclusion in this program and expedite funding for pending water body restoration projects.

Water is not just a resource; it is a fundamental right. The people of Palnadu and other drought-prone regions of Andhra Pradesh have suffered for far too long. With the NDA back in power and with the strong leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu, we must accelerate our efforts to provide water security to every household. Let us ensure that the policies and schemes meant to transform water governance do not remain mere announcements but translate into tangible benefits for the people. I urge the Government to prioritize the completion of the Polavaram Project, expedite pending irrigation projects, ensure timely fund disbursal for water schemes, and reinforce Andhra Pradesh?s water security for a prosperous and sustainable future.

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR):

Budget alloction to the Ministry of Jal Shakt (in Rs. Crore)				
Department	2023-24Actual	2024-25 RE	2025-26 BE	% change from 24-25

				RE to 25-26 BE
Drinking Water and Sanitation	76,570	29,917	74,226	148%
Of which				
JJM (Jal Jeevan Mission)	69,992	22,694	67,000	195%
SBM-G (Swachh Bharat Mission)	6,546	7,192	7,192	0%
Water Resources	18,539	21,641	25,277	17%
Of which				
PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojana)	6,088	6,621	8,260	25%
River Interlinking	1,922	3,000	3,400	13%
Namami Gange	1,391	2,000	2,400	20%
ABY	1,739	600	1,780	197%
Total	95,109	51,558	99, 503	93%

Jal Jeevan Mission - A Revolution in ensuring Right to Water

For 70 years no Prime Minister ever thought about ensuring the right to water to people of this country.

It was PM Modi ji who first thought about providing tap water connection to every household and thereby ensure Right to Water.

The Jal Jeevan Mission (JJM) launched in August 2019, with an aim to ensure long-term water security to rural households by providing reliable access to safe piped drinking water has been a revolution by itself.

When it was launched in August 2019, only 3.23 crore (17 per cent) of rural households had tap water connections. Since then, over 12.06 crore families have been added, increasing the total to more than 15.30 crore (79.1 per cent) out of approximately 19.34 crore rural households as of November 26, 2024.

Krishna Pennar River Linking Project to bring water to Chikkaballpaur, Kolar and Bangalore Rural

- I represent Chikkaballpaur Lok Sabha Constituency which is a water scarce region.
- With no perennial source of water, the entire Bayaluseeme region comprising of Chikkaballpaur, Kolar and Bangalore Rural districts are dependent on rains and underground water, both for drinking and irrigation purposes.
- As per the norm, every citizen should get 150 litres of water per day (LPCD).
- In Kolar and Chikballapur, people get around 40 to 60 LPCD. This is the situation.
- Bengaluru needs 1,300 million litres of water per day (MLD) and is largely dependent on Krishna Raja Sagar reservoir.

- Kolar needs 160 MLD and Chikballapur needs 150 MLD; both are largely dependent on groundwater. But in Bengaluru, each person gets only around 70 LPCD.
- The depleting ground water levels in Chikkaballapur, Kolar, Tumakuru districts makes it imperative to find a permanent solution for irrigation woes of farmers in the region.
- The construction of a canal from Krishna River in neighbouring Andhra Pradesh to transport at least 5 tmc ft water to the bayaluseeme region could be a potential solution which will immensely benefit the Chikkaballapur, Kolar and Bangalore Rural districts and will also reduce the burden on Cauvery, which is the only major source of water to Bangalore city.
- I also urge the Jal Shakti Ministry to come up with special catchment area development plans along Palar, Pennar and Chitavrati rivers areas and rejuvenation of small river bodies in the region.
- The budget for interlinking river is only Rs.3,400 crores
- I request the Govt to include this Interlinking of River Project under the National Perspective Plan (NPP) which will immensely benefit the Krishna River basin in Kolar and Chikkaballapur districts of Karnataka.

  Regards.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAGAON): The importance of water in all spheres of life and the economy - from agriculture to manufacturing - cannot be understated. This makes it even more crucial that the government?s water policy and any schemes related to it are implemented properly and account for current challenges like climate change and rampant pollution of India?s water sources. Unfortunately, this budget fails to recognise this. It is alarming that while the ministry was allotted close to Rs. | lakh

crore in last year?s budget, the revised estimates stands at only a little over Rs. 50 thousand crore - pointing towards dismal utilisation rates.

The Government?s inability to implement its own schemes are particularly showcased by the failure of the Jal Jeevan Mission. While the Government had promised to provide functional tap connections to all rural households by 2024, several states have already extended the deadline to as far as 2027. Even more painful is that my own state of Assam?s implementation of JJM has been disappointing. As of now, over 18% of villages have not received functional tap connections meaning that Assam is the worst performing state in the North East except for Manipur. Corruption in the scheme?s implementation is so rampant that the state government even had to suspend all JJM projects in October last year and conduct a financial audit.

Next, the Brahmaputra and its associated tributaries are the lifeline of the North East but have been utterly neglected by this government. River bank erosion has emerged as a pressing problem that must be urgently addressed and it is estimated that since 1950, Assam has lost close to 7.5% of its land area to this. This Government, however, has ignored all the warning signs and has failed to take adequate measures. The Brahmaputra Board, in charge of preparing Master Plans for the river?s management and Detailed Project Reports for multipurpose projects on it suffers from extremely high vacancies. Moreover, the Board lacks a formal mechanism to monitor the implementation of the plans and reports it prepares. It is thus clear that the Board must either be reformed or replaced - a demand | had made in my budget speech last year. Apparently, the Government is aware of this too - in 2021 and 2023, in submissions before the Parliamentary Standing Committee on Water Resources, it had said it was planning to establish a North East Water Management Authority or NEWMA to carry out the integrated

management of the Brahmaputra and Barak river basins. In May 2023, the hon?ble Union Minister for Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, while addressing a press conference in Guwahati even promised the establishment of the NEWMA. Close to 2 years on from then, this promise remains un-fulfilled.

Lastly and most importantly, | would like to register my alarm regarding reports, from December last year, that China had approved a hydroelectric dam billed to be the largest hydropower project in the world on the upper stream of the Brahmaputra, or Yarlung Tsangpo as it is known in Tibet, at the ?Great Bend?, the region where the river takes an abrupt Southward turn before entering Arunachal Pradesh. We have reason to believe that if constructed, such a dam wouldallow China to ? weaponise? water against us. The Brahmaputra, accounting for 30°o of India?s freshwater resources, is the lifeline of the North East, providing the region with abundant water and fertile silt, as reflected in the immense cultural significance it holds. Such a dam would reduce water flows in the river, triggering droughts during the dry season. It could also permanently disable the annual flooding cycle that supplies the fertile silt that much of Assam depends on. On the other hand, China might use the dams to induce flooding by suddenly releasing large amounts of water without warning. In 2000, floods in Arunachal and Himachal Pradesh that caused widespread destruction and loss of life were attributed to this. In fact, Arunachal CM Pema Khandu has already warned of the possibility of China creating ?water bombs? that will wreak havoc on the North East if the dam is constructed. China?s unreliable data sharing habits are also an immense cause for concern. The MoUs we had signed with the Chinese government for hydrological data sharing expired in 2023 and even when they were in place, they were not legally binding. In 2017, China deliberately withheld data in the backdrop of the Doklam standoff

while supplying the same to Bangladesh. The dam would also pose a major _ threat to India?s sovereignty. I thus urge the Ministry to immediately conduct surveys and assessments on the adverse environmental impacts such a dam, if built, would have on downstream states like Arunachal Pradesh and Assam, including whether it would exacerbate the effects of flooding and river erosion in the North East.

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : माननीय सभापित महोदया जी, मैं जल शक्ति मंत्रालय के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदया जी, जल शक्ति मंत्रालय का बजट 2025-26 बहुत अच्छा है जो भारत सरकार की जल संरक्षण, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं के महान संकल्प को दर्शाता है । पर हमारे DNH और DD प्रशासन की अनियमित कार्य - पद्धिति के चलते सरकार के इस महान संकल्प का सर्वनाश हो रहा है ।

जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी ने एक बार इस संसद में हमारे प्रदेश को लेकर घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश ने जल जीवन योजना के तहत 100 प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त की है । हालांकि, मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है, कि माननीय मंत्री जी का बयान पूरी तरह से वास्तविकता से परे है । आज भी DNH और DD के UT में हजारों घर ऐसे है, जहाँ पीने योग्य, स्वच्छ पेयजल पहुंचा ही नहीं है ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हर locality/society जहां 50 फ्लैट हो वहां एक कनेक्शन स्थापित करना, संतृप्ति का संकेत नहीं माना जाना चाहिए ।

कुछ localities में, लगभग 80 प्रतिशत घरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है । सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, कि हर एक locality में हर एक घर को एक कार्यशील नल का पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाए ।

महोदया जी, हमारा प्रदेश समुद्र की गोद में बसा हुआ प्रदेश है, जहां मीठा भूगर्भ जल की बहुत कमी है, जिसमें भी बढ़ते प्रदूषण के कारण भूगर्भ का जल भी बहुत प्रदूषित हो चुका है, हमारे प्रदेश के ज्यादातर बोरवैल का पानी पीने के लायक नहीं रहा

है, और ज्यादातर बोरवैल के पानी गर्मी की शुरुआत होते ही सूख जाते हैं, ऐसे तो पूरे DNH और दमण दीव में साफ पानी की भारी किल्लत हो रही हैं, आए दिन पानी के लिए बुमा-बूम हो रही हैं । हमारे प्रदेश की बहनें पानी की समस्याओं को लेकर अब P.W.D. की ऑफिस तक पहुंचने लगी हैं । पहले जिनके घर नल से जल आता था वे भी विकास कार्य की बलि चढ़ गए, हमारे प्रदेश की बिना प्लानिंग एवं विभागों के आंतरिक संकलनों के अभावों में ज़्यादातर विकास कार्य सालों साल तक चलता ही रहता है । जहां देखो वहां खुदाई ही चल रही है, हमारे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए नया फंडा निकला है, हमारे प्रदेश में सालों - साल से बने बनाए सड़कों को 3 फिट से 5 फिट खोद दी जाती हैं जिसके चलते आए दिन पानी की पाइप लाइन तोड़ कर रख दिया जाता है । मैडम, मुझे दो ही मिनट बोलते हुए हुआ है, दो मिनट और बोलने के लिए दे दीजिए ।

माननीय सभापति : आप एक मिनट में कम्प्लीट कीजिए ।

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल : कई जगह तो पूरी की पूरी पाइपलाइन ही तोड़ कर फेंक दी गयी हैं, रास्ते का कार्य पूर्ण होने पर पता चला की पानी की लाइन तो डाली ही नहीं गई है । काफी सारे ऐसे निर्माण कार्य है, की पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं, जो 4 से 5 साल तक एक ही जगह चलते रहते है । सब विभाग साथ मिलकर संकलन कर काम नहीं करते । इसके चलते पानी की लाइनें कट जाती हैं और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है ।

महोदया जी, एक तरफ प्रदेश के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, और हमारे मंत्रीजी हमारे प्रदेश मे 100 प्रतिशत जल आपूर्ति की बात करते हैं, पर भूल हमारे माननीय मंत्री जी की नहीं है । हमारे प्रतिनिधियों ने हिम्मतनगर के भ्रष्टाचारी अलीबाबा के दबाव में आकर लिखकर दे दिया था, कि हमारे प्रदेश में 100 प्रतिशत प्रतिशत लोगों के घर नल से जल पहुंच गया है ।

हमारे प्रतिनिधियों ने हिम्मत नगर के भ्रष्टाचारी अलीबाबा के दबाव में आकर लिखकर दे दिया था कि हमारे प्रदेश में 100 प्रतिशत लोगों को उनके घर पर नल के द्वारा जल पहुंच गया है । उनसे लिखवाकर भ्रष्टाचारी अलीबाबा ने शायद सरकार से अवार्ड भी ले लिया होगा । प्रदेश के लोग पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रहे हैं ।

महोदया, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वह हमारे संघ प्रदेश में जल-जीवन मिशन की स्थिति का एक व्यापक पुन: सर्वेक्षण करे । इसके अलावा मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वह दमन और दीव में जल-जीवन मिशन कार्य्रकम को पूरा करने के लिए एक नई कार्य-योजना विकसति करे, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके । धन्यवाद ।

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): Thank you, Madam, for allowing me to participate in this discussion.

I congratulate our honourable Prime Minister Shri Narendra Modi and Minister for Jal Shakti Shri C R Patil for this budget, in which ₹99,503 crores have been allocated for the ministry of Jal Shakti for the financial year 2025-26. This reflects their dedication towards ensuring water security for our country. For the last few years, we can see the dedication of the Union Government to deal with the water problems in our country.

I am speaking on behalf of Anantapur district which is the 2nd lowest rainfall recorded region in India. Anantapur is part of the Rayalaseema region, which is known for tolerance and courage. This region has been facing a severe water crisis for the last several decades. Between 2014-19 our chief minister Nara Chandrababu Naidu made efforts to address the water crisis in this region. Micro irrigation projects and drip irrigation projects were encouraged in this area to deal with the water crisis.

Under NTR Jala Siri program SCs and STs were provided with 90% subsidy and others were provided with 80% subsidy. Godavari and Krishna rivers were inter-linked by completing Pattiseema project in record time. By completing 80% works of Handrineeva Sujala Sravanthi project, waters of Krishna were brought to Anantapur, Kadapa, Kurnool and Chittoor districts. 70% of Polavaram project works were completed. But the previous state Government could not complete the remaining

20% work of the Handrineeva project and they also diverted funds released by the Central Government for the Polavaram project to other schemes.

We constructed projects but they neglected them. People of Andhra Pradesh realised that we worked for farmers and the previous government completely neglected farmers. Now, Nara Chandrababu Naidu has become chief minister of Andhra Pradesh again and the Polavaram project work is on track. I would like to thank the union government for allocating ₹12,157 crores for the Polavaram project. We have a clear goal to complete the first phase of the polavaram project by June 2026 and provide irrigation facilities to our farmers. For Handrineeva project also the state government has provided ₹963 crores and tenders have been floated for remaining works of that project. We are working with a goal to provide water to the Rayalaseema region by next June.

There is one more important project for Rayalaseema to interlink rivers under the Polavaram and Banagacharla project, for which we seek support from the union government. As per the vision of our chief minister Nara chandrababu naidu the excess water of Godavari will be diverted through Krishna river to Penna, for which we have to construct a reservoir at Bollapalle in Guntur and Banagacherla in Nandyal district, which will provide drinking water to 80 lakh people and irrigation facilities to 7.5 lakh acres of land. We seek full support for this project from the central government. This project will cost around ₹80,000 crores.

There is a need to focus on the command area development scheme, because, ₹1,400 crores were allocated for the year 2024-25, but till now not even a single rupee could be spent. As the funds for the command area development scheme have been reduced to ₹850 crores,

the central government will have to take appropriate steps to utilise these funds fully. Similarly, Jal Jeevan Mission has completely transformed the drinking water facility in rural areas. Due to the negligence of the previous state government less than13% of allocated ₹16,508 crores of funds could be used in our state. Now new DPRs have been prepared and we are hopeful that the mistakes committed by the previous government can be undone now.

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): The Ministry has been allocated a fiscal outlay of Rs. 99,543 crore, which comprises 0.28% of the total expenditure budget for FY2025-26.

The budget expenditure for the Ministry has increased by 4.64% and 1% compared to the budget estimates (BE) and revised estimates (RE), respectively, for FY2024-25.

Of the total outlay (Rs. 99,543 crore), Rs. 25,277 crore has been allocated for the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, and Rs. 74,266 crore has been earmarked for the Department of Drinking Water and Sanitation.

The Government has shown that the budget for the Department of Drinking Water and Sanitation has increased by 148% i.e. Rs. 74,266 in BE 2025-26 from RE 2024-25; but I would like to state that in AE 2023-24 Department of Drinking Water and Sanitation budget was Rs. 76,570, in BE 2024-25 Department of Drinking Water and Sanitation budget was Rs. 77,391 and then in RE 2024-25 the Government slashed the Department of Drinking Water and Sanitation budget to Rs.29,971 first the Government slashed the budget & now the Government is showing 148% hike but in comparison the budget is still lower as compared to the amount in AE 2023-24 as well as in BE 2024-25.

Only Rs. 51,558 crores out of the budget expenditure of Rs. 98,714 crores were utilised. That means that the Ministry spent just over half the budget (52%) it had been allocated. This is why the increase over RE is as high as 93%.

While launching the Swachh Bharat Mission in 2014, the Government aimed to eliminate open defecation by 2019. This target is yet to be achieved. Subsequently, the Government set itself the target of providing tap water connection to all rural households by 2024. Failing to meet this deadline, the government has revised the target to 2025.

The Modi Government has become infamous for missing and revising deadlines set by themselves. The Government has also missed its targets for Waste Management.

Jal Jeevan Mission is a complete failure. No clean drinking water is supplied through this scheme.

I would like to state that only two sources of water is made available in my Gadchiroli Lok Sabha constituency one through bore well & secondly from River Water & in both the cases no filtration or purification plants are made available & without purification the consumption of water is dangerous to health.

Most of the works of laying pipelines are incomplete; the contractors have not been paid as a result the work is abandoned.

No proper utilization of water for agricultural purposes is seen in my constituency because all the major, medium & minor dams which were proposed for years back have not yet been either started or completed.

To name a few: -

1. Karwafa Medium Project in Dhanora tehsil Work need to be done at 5250 hectare of land which will benefit 25 villages. Forest land required

-569.72 hectare.
2. Duminala Small Project in Etapalli Work needs to be done in 2400 hectare of land which will benefit 11 villages, Forest land required - 366.84 hectare.

3. Durkangudra Small Project in Dhanora - Work needs to be done on 1213 hectare of land. Forest Land required is 95.912 hectare.
4. Pipari Rith Small Project in Chamorshi - Work needs to be done on 480 hectare of land which will benefit 5 villages. Forest land required is 176.22 hectare.
5. Pulkhal Small Project in Dhanora - Work needs to be done in 281 hectare of land which will benefit 3 villages. Forest land required is 77.685 hectare.
6. Tultuli Medium Project in Armori Work needs to be done in 36,772 hectare of land. Forest land required is 2228.06 hectare.

7. Chenna Medium project in Mulchera Work needs to be done in 2342 hectare of land. Forest land required is 372.74 hectare.

All the above mentioned projects require 3887.177 hectare of forest land, but the Government has completely failed to complete the irrigation projects in my Lok Sabha Constituency due to want of forest clearances & other unknown reasons.

Due to incomplete projects, people of my Lok Sabha Constituency are facing acute water scarcity and lakh of farmers are suffering.

How can this ministry be called as Jal Shakti - there is a lot of Jal but no shakti.
No irrigation facilities are made available to my constituency, the farmers are to be dependent on the natural rainfall which affects crops adversely as a result the farmers take only one crop in a year.

Rivers in Gadchiroli Dist. & my Gadchiroli-Chimur Loksabha constituency are Godavari, Wainganga, Khobragadi, Kathani, Mirgadola, Pranhita, Dina, Indravati, Wardha, Parlkota, Kotari, Gadhavi, Chenna, Siwani, Darshani.

Bagh River in Amgaon constituency, Wardha & Penganga in Brahmapuri constituency.

Small barriers need to be built between the above-mentioned rivers in order to regulate water flow & support agriculture, industry as well as waste management.

Only one major dam Tultuli is proposed by the central government on Khobragadi river and that too is incomplete.

I request the Hon'ble Minister to look at the above mentioned facts' and give necessary instructions to the officials concerned to get the irrigation projects in my Lok Sabha constituency completed which are stuck due to want of forest clearances & other reasons.

Provide clean drinking water for the people of my Gadchiroli-Chimur Lok Sabha Parliamentary Constituency and as mentioned before build small barriers between the above-mentioned rivers.

श्री नारायणदास अहिरवार (जालौन) : जल जीवन मिशन के तहत बुन्देलखण्ड के साथ मेरे लोक सभा क्षेत्र जालोन अब तक कितने घरों में जल से स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिशिच की जा चुकी है ।

केन वेतवा लिंक परियोजना कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस परियोजना से बुन्देलखण्ड के किन किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा ।

एरच बांध परियोजना के तहत कितने गांव में बिजली, सिंचाई और पेयजल की अब तक कितनी सुविधायें उपलब्ध करायी गई हैं और परियोजना पूर्ण होने को संभावित समय सीमा क्या है ।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I would like to express my views on the Demand for Grants for the Ministry of Jal Shakti for the year 2025-26. I rise on behalf of my party strongly support this demand, and I begin by congratulating Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Hon'ble Minister for Jal Shakti Shri C.R. Patil ji for presenting a robust budget of 299,503 crore this year for the Ministry-an increase from last year. This clearly reflects the Government's unwavering commitment to ensuring Har Ghar Jal and Har Khet Ko Paani.

Out of this, Rs.25,276 crore has been allocated to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, and Rs.74,226 crore to the Department of Drinking Water and Sanitation. The Government's efforts in water conservation, sanitation, and integrated water management have transformed India's approach to its most vital resource-water.

I would especially like to highlight and appreciate the outstanding achievements of the state of Odisha, which has emerged as a national leader in water management and conservation. Odisha was declared the top performer in the 5th National Water Awards 2023. This recognition is not symbolic-it is backed by substantial and measurable action on the ground.

Odisha has successfully constructed over 53,000 water conservation and rainwater harvesting structures, rejuvenated 11,000 traditional water bodies, and set up 21,000 wastewater treatment facilities. Furthermore, the state has transitioned more than 90,900 hectares of land to micro-irrigation systems, directly benefiting over 87,000 farmers. These are not just numbers-they represent transformed lives, enhanced farm productivity, and improved groundwater recharge.

Odisha has also set a target that by March 2027, it aims to achieve 100% functional tap water connections in all rural households across every district. This ambitious yet credible target aligns with the vision of Jal Jeevan Mission, under which the national coverage has increased from 17% in 2019 to nearly 80% today. Odisha's leadership in this mission must be acknowledged and celebrated.

Under the Swachh Bharat Mission Grameen (SBM-G), Odisha has made remarkable progress. Nationwide, over 11.77 crore Individual Household Latrines and 2.49 lakh Community Sanitary Complexes have been built since 2014. Odisha has significantly contributed to this effort, with a strong focus on rural sanitation and solid & liquid waste management.

The number of ODF Plus Villages across India surged from 1 lakh in December 2022 to over 5.61 lakh villages by December 2023. Odisha played a critical role in this success through community participation and robust implementation. Solid waste management arrangements now exist in over 4.75 lakh villages, and liquid waste management systems in 5.14 lakh villages, with Odisha being one of the forerunners.

The Government has also promoted the GOBARdhan scheme, under which more than 990 community biogas plants are functional, promoting waste-to-wealth and clean energy. Odisha has been proactive in this initiative as well, establishing biogas systems that reduce dependency on firewood and improve sanitation.

I would also like to bring attention to the importance of integrating water quality with access. The Ministry has ensured that out of the 2,180 water testing laboratories in the country, over 1,580 labs have NABL accreditation. Odisha is steadily increasing its presence in this area, enhancing trust in rural water supply schemes.

The Atal Bhujal Yojana, Namami Gange, PM Krishi Sinchayee Yojana, and Jal Jeevan Mission-all collectively reflect a comprehensive vision for water security. Odisha's success under these programmes proves that when political will, community ownership, and proper execution come together, transformational change is possible.

? I urge the Government to replicate Odisha's best practices in other states and to provide additional performance-based incentives to states like Odisha that have shown excellence in water governance.

? To conclude, water is not just a resource, it is a source of life, dignity, and development. Odisha has demonstrated how state-led commitment and Centre-state cooperation can ensure inclusive and sustainable water solutions. I strongly support this Demand for Grants and look forward to continued and expanded support for Odisha's water and sanitation ecosystem.

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदया, आपने जलशक्ति मंत्रालय पर मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए धन्यवाद ।

महोदया, जब यह जल-जीवन मिशन योजना शुरू हुई, तो देश की आम जनता ने आस लगाई, जो महिलाएं वर्षों से दो-तीन किलो मीटर तक पैदल चलकर अपने सिर पर बर्तन रखकर पानी लेकर आती थीं, उन्होंने आस लगाई कि वर्ष 2024 तक जल-जीवन मिशन के तहत हमारे घर में पानी आ जाएगा । मैं भी तत्कालीन विधायक था । मैंने भी विचार किया कि हम हैंडपम्प, बोरिंग खोदकर क्या करें? जल-जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में पानी आ जाएगा, लेकिन हकीकत क्या हुई?

लेकिन हकीकत में क्या हुआ? हकीकत में यह हुआ कि वह महिला आज भी पानी के लिए तरस रही है, जिसने सपना देखा था कि वर्ष 2024 तक पानी आ जाएगा और जिस गति से काम हो रहा है, और अभी जो काम हुआ, उस हिसाब से लग रहा है कि

वर्ष 2038 तक भी यह काम पूरा नहीं हो पाएगा और आपने वर्ष 2047 तक का भी वादा कर दिया है ।

सभापति महोदया, हमने देखा है कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है । भेदभाव इंसान करता है, लेकिन सरकार भी जाति समूह देखकर भेदभाव करती है और यह आँकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान के अंदर 17 लाख 40 हजार आदिवासी परिवार रहते हैं, उनमें से 5 लाख 7 हजार आदिवासी परिवारों के घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं, वे मात्र 29 प्रतिशत हैं और हकीकत में धरातल पर मात्र पांच प्रतिशत आदिवासी परिवारों के घरों में पानी गया है । जिस तरह से यह भेदभाव हुआ है, उससे हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समुदाय, जो ग्रामीण इलाकों में रहता है, उसके साथ सरकार हमेशा भेदभाव करती है । सरकार की यह मंशा होनी चाहिए कि सबसे पहले गरीब, ग्रामीण और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर इस योजना को तेज गति से लागू करे ।

सभापति महोदया, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है इसलिए हमारा क्षेत्र नए भील प्रदेश की मांग करता आया है । अगर मैं गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की स्थिति बताऊं तो गुजरात में 20 लाख 50 हजार आदिवासी परिवारों के घर हैं । सरकार दावा कर रही है कि 100 परसेंट घरों के अंदर पानी पहुंच गया है । मैं खुद महिसागर, साबरघाटा, विजयनगर, भीलूडा, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के नजदीक पड़ते हैं, वहां पर गया हूँ । वहां पर कई ऐसे घर हैं, जो एक-एक किलोमीटर से पानी लेकर आ रहे हैं ।

अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पर 50 प्रतिशत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया है । झारखंड में 27 प्रतिशत, केरल में मात्र 36 प्रतिशत, वहीं पश्चिम बंगाल में 46 प्रतिशत पानी ट्राइबल इलाकों में पहुंचाया गया है ।

राजस्थान में हमने पिछली सरकार में 886 करोड़ की कडाना से गेजी घाटा तक पेयजल परियोजना स्वीकृत करवाई थी, लेकिन वर्तमान में हमारी जो राजस्थान की सरकार है, वह विकासवादी कम लगकर विकासविरोधी ज्यादा लगती है । उसने इस योजना पर रोक लगा दी है ।

सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि यह 886 करोड़ रुपये की कडाना बैकवाटर परियोजना, साथ ही घाटोल व बांसवाडा के लिए 620 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत है, उसे शुरू करवाया जाए और बेनेश्वर एनिकट से सागवाडा और सांबला के लिए भी इस परियोजना को स्वीकृत किया जाए ।

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Madam, I rise to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Jal Shakti. मैडम, हमने हमेशा सुना है कि जल ही जीवन है । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान केवल जल संरक्षण में ही है । जल है तो जीवन है, जल है तो कल है । Jal Shakti Mission aims for a water-secure India, but the progress has been limited. Groundwater is depleting, millions lack drinking water, and key projects are stalled. The NITI Aayog itself reports 70 per cent of India?s water to be contaminated. The Government fails to fully utilise the budget and meet the targets, and refuses to support the crucial State-Centre water projects. In Karnataka, projects like Upper Bhadra, Godavari-Krishna-Cauvery water sharing, Mekedatu, and Kalasa Banduri Nala still await the Central Government?s backing.

In Karnataka, we have aptly identified this *Sarkar,* and by extension, their Jal Shakti Mission as *khali chombu.*

Madam, let me share a few of the alternate facts the Centre uses. The Government claims that 80 per cent of the households have tap water under the JJM but in reality, only 62 per cent of these connections are fully functional, and meet the 55-litre daily quota. Despite this, the JJM faced a 68 per cent budget cut in 2024-25, highlighting under-utilisation of funds. The Government claims that Atal Bhujal Yojana improved water conditions in 8,000 water-stressed panchayats but only 37 per cent of the regions got the benefits, and just 57 per cent of the budget was utilised. Let me repeat, only 57 per cent of the budget was utilised.

I am concerned about the declining groundwater table in urban areas as well. I urge the Ministry to address this issue both in the urban and rural areas. कुएं में तो पानी है, लेकिन बाल्टी या बर्तन को भरने का भी सामर्थ्य इस सरकार में नहीं है ।

Madam Chairperson, the Government consistently fails to utilise the budgeted Jal Shakti funds year-on-year. They have themselves budgeted the funds. Why do they not direct these funds to the States which they repeatedly overlook?

Karnataka only gets Rs. 13 for every Rs. 100 we contribute to the Centre?s coffers. Karnataka ranks 22nd out of 34 States/UTs in JJM. In the financial year 2024-25, the Centre allocated Rs. 3,804 crore under JJM for Karnataka but has released only Rs. 570 crore, while the State spent Rs. 4,977 crore, exceeding the agreed-upon 60:40 Centre-State ratio.

Despite repeated appeals and protests, the Centre has not released further funds while Karnataka has fulfilled its commitment. This is plain authoritarianism. We Kannadigas work hard and pay taxes only for the Centre to pocket Rs.87 out of every Rs.100. This is unjust. .... *(Interruptions)*

Madam, I would like to revisit a request I have repeatedly made in the past Sessions, to support the Upper Bhadra project. This project supports the irrigation of two lakh hectares of land in four districts of Karnataka, namely, Chikmagalur, Chitradurga, Tumkur and Davangere. The Centre had announced Rs.5,300 crore for the project but, as I mentioned earlier, they have not delivered it. ....*(Interruptions)*

Madam, I will just conclude in a minute. ....*(Interruptions)* *I would request the Central Government through you for a grant of Rs. 150

crores to irrigate lands of nearly 5,700 hectares, through the tail ends of Bhadra canal in rural areas of Harihara, Malebennur Davanagere and Hosasalli.*

Finally, I would request the hon. Minister to release the long-standing dues to Karnataka immediately to ensure that budgeted allocations are properly utilized.

जल है तो कल है ।

With these words, I conclude. Thank you.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, जी. सेल्वम जी ।

माननीय श्री आनंद भदौरिया जी ।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : महोदया, मैं न चाहते हुए भी कहना चाहता हूं कि जल शक्ति मंत्रालय का नाम बदलकर धन संचय मंत्रालय रख देना चाहिए, क्योंकि कहीं बाढ़ है, तो कहीं सूखा है । वहां न बाढ़ का प्रबंध है और न ही सूखे का इंतजाम है । चाहे नदी जोड़ने की परियोजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन का बजट हो, चाहे जल संसाधन का बजट हो, चाहे नमामि गंगे का बजट हो, या अटल भूजल योजना का बजट हो, हर मोर्चे पर सरकार विफल हुई है । अगर आप नदी जोड़ना सीखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने गोमती नदी रिवर फ्रंट का जो मॉडल दिया था, उस मॉडल को सरकार को अपनाना चाहिए ।

सभापति महोदया, जल जीवन मिशन, आजादी के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, अगर किसी विभाग में हुआ है, तो वह इस विभाग में हुआ है । भ्रष्टाचार की ? * जो दिल्ली से चली, उत्तर प्रदेश पहुंचते-पहुंचते पूरी ?* उस भ्रष्टाचार में डूब करके आकंठ तक लबालब हो गई ।

सभापति महोदया, हमारे क्षेत्र में महोली में एक चितला गांव है, वहां पूरी की पूरी टंकी गिर गई । आपने वहां पूरी सड़कें खोद कर पाइप लाइंस डाल दी हैं । आपने वहां जो टूटी लगाई है, उसमें पानी नहीं आ रहा है । आप वहां बाल्टी रख दीजिए, लेकिन पूरे दिन में बाल्टी नहीं भरेगी । ? (व्यवधान) मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म कर रहा हूं ।

बाढ़ का यह आलम है कि उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में बारिश के पानी से बाढ़ आ जाती है और वहां नाव चलानी पड़ती है ।

सभापति महोदया जी, मैं आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । गंगा सफाई के नाम पर जो बजट दिया गया ।? (व्यवधान)

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 सालों बाद भी प्रयागराज की धरती, बुंदेलखंड की तरह हमारा इलाका है, वहां पठारी क्षेत्र भी है, वहां पहाड़ी क्षेत्र भी है, लेकिन वहां टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है । मैं कहना चाहता हूं कि शंकरगढ़ टाउन एरिया है, जहां गर्मियों के मौसम में टैंकर्स से पानी दिया जाता है । जल शक्ति मंत्रालय का पैसा कहां जाता है, यह पता नहीं चलता है?

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बड़ोखर एक ग्राम सभा है । वह एकदम मध्य प्रदेश से लगा हुआ है । वहां पर भी पानी की सप्लाई टैंकरों से होती है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में न पीने का पानी है और न ही सिंचाई के लिए पानी है, तो वहां लिफ्ट कैनाल की व्यवस्था होनी चाहिए । यह लाल बहादुर शास्त्री जी का क्षेत्र है, जहां से देश के प्रधानमंत्री चुनकर यहां आते रहे हैं । मैं इस क्षेत्र की बदहाली का हाल बयां करना चाहता हूं । यहां पर लिफ्ट कैनाल बननी चाहिए । टुड़ियाल लिफ्ट कैनाल को बढ़ा कर बड़ोखर को सिंचित करना चाहिए । मझगवां न्याय पंचायत में एक लिफ्ट कैनाल बनानी चाहिए और देवघाट में एक लिफ्ट कैनाल बनानी चाहिए ।

हमारे इलाके में ब्लास्टिंग कूप बनाना चाहिए और चैक डैम बनाना चाहिए । जहां गंगा बहती है, जहां यमुना बहती है, वहां पानी का अभाव है । मैं जलशक्ति मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रयागराज के क्षेत्र को बुंदेलखंड जैसी सुविधाएं दी जाएं और ज्यादा से ज्यादा पीने और सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाए । लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र को भी देखने का प्रयास करें ।

धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार ।

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर):

जल है तो जीवन है
नहीं तो त्राही माम है
त्राही माम है

परन्तु आज मोदी ही है तो मुमकिन है । इसलिए इस बात को यूं कहेंगे-
शुद्ध जल मिला नव जीवन की ।
अब सार्थक सुजलाम् सुफलाम् भारत का नाम है ।
भारत का नाम है ।...

मैं केंद्रीय बजट 2025-26 की सांग संख्या 62 एवं 63 का समर्थन करता हूं । मांग संख्या 62 में 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान 2024-25 की तुलना में लगभग ढाई सुन्ता अधिक बजट का प्रस्ताव किया है । एवं मांग संख्या 63 में 2024-25 के संशोधन अनुमान की तुलना में लगभग 178 प्रतिशत बजट बढ़ा कर दिया है । यह दिखाता है कि मोदी जी की सरकार जल संसाधन, नदी विकास, नमामि गंगे, पेयजल व स्वच्छता के कार्यक्रमों को बहुत समर्थन देती है । इसके लिए केंद्र सरकार का बहुत-बहुत अभिनंदन ।

73वां स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 2019 का दिन भारत में जल संसाधन के लिए ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है । क्योंकि इस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के ग्रामीण परिवारों को नल से जल देने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की थी । यह अदम्य साहस का कार्य था ।

ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अदम्य साहस क्या है?

इसी संदर्भ में देखें तो अदम्य साहस के दो पहलू हैं । एक है वह दृष्टि जो उपलब्धि के उच्चतर लक्ष्यों की ओर ले जाती है । मुझे संत कवि तिरुवल्लुवर के 'तिरुक्कुरला की 2200 साल पहले लिखी गई दो पंक्तियाँ याद आती हैं,

?Vellaththu anaiya malarneettam maanthartham

ullaththu anaiyathu uyarvu.?

इनका अर्थ है: "नदी या झील या तालाब की गहराई कितनी ही क्यों न हो और उसका पानी कैसा भी क्यों न हो, कमलिनी खिले बिना नहीं रह सकती । इसी तरह, अगर किसी लक्ष्य तक पहुंचने का पक्का इरादा कर लिया जाय, तो चाहे वह कितना ही असंभव क्यों न हो, इंसान उसे हासिल कर ही लेता है ।"

इस मिशन का लक्ष्य देश के सभी ग्रामीण परिवारों और सार्वजनिक संस्थाओं जिसमें विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, आदिवासियों के लिए संचालित है छात्रावास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, अन्य सामुदायिक केंद्र, ग्राम पंचायत के भवन आदि में नल से शुद्ध जल पहुंचने का लक्ष्य रखा जो 2024 में पूर्ण होना था । विविध कारणों से यह लक्ष्य अब 2028 है ।

इस मिशन की पहुंच को देखें तो 2019 में ग्रामीण भारत में लगभग 19 करोड़ परिवारों में मात्र 17% परिवारों तक ही नल से जल के कनेक्शन थे । ग्रामीण भारत और ग्रामीण शहरी भारत में पेयजल की सुविधाओं में यह अंतराल चुभने वाला था परंतु सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, व सबका प्रयास की रीति पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण भारत में भरोसेमंद जल स्रोतों को पहचानने का लक्ष्य रखा ।

जल जीवन मिशन भारत सरकार का के सबसे बड़े सामुदायिक बुनियादी ढांचे में से एक है ।

यह बॉटम अप अवधारणा के आधार पर विकेंद्रीकृत तरीके से लागू किया जा रहा है । यह मिशन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना अनुसार यह धरातल पर स्व-शासन के अधिकार को भी जीवंत कर रहा है ।

यह मिशन बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के अनुरूप हुई है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को धरातल पर स्थापित करता है । जीवन जीने के मूलाधिकार को भी स्पष्ट करता है । एवं नागरिकों मे गरिमामय जीवन जीते हुए समान अवसर को भी सुनिश्चित करता है । साथ ही यह मूल कर्तव्यों के अनुसार नदी, जल व झीलों की रक्षा एवं प्राणी मात्र के लिए जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है ।

जल हमारे जीवन के सभी आप सभी की पूर्ति के लिए आवश्यक है एवं स्थिति की प्रणाली और मानवीय गतिविधियों का अहम पहलू है विषम परिस्थितियों हैं परंतु सिंचाई उद्योग एवं पेयजल के लिए इसकी बड़ी उपलब्धता चाहिए है ।

इस साहसिक कार्य में एक तेलगू कवि गुर्जादा की भी प्रेरणा है

मेरे भाई । यह देश तुम्हें प्रिस है

तुम इसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाकर,

इसके सुधार में लगे रहें । साहसिक कार्यों की आवश्यकता है आज ।

जल जीवन मिशन घोषणा की 73वें स्वतंत्रता दिवस से 77 में स्वतंत्रता दिवस तक पहुंचते-पहुंचते हैं इस मिशन की उल्लेखनीय प्रगति पाई है ।

जनवरी 2025 तक नल से जल की आपूर्ति 19 करोड़ में से 15:43 करोड़ अर्थात कुल ग्रामीण परिवारों की 17% से बढ़कर 80% तक पहुंच चुकी है । यह स्वाधीनता की बाद सबसे बड़े बदलाव की बड़ी झलक है । इसके लिए कर्मयोगी प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः अभिनंदन है ।

भारत भर में जल जीवन मिशन की प्रगति यदि देखें तो 8 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में शत प्रतिशत परिवारों तक नल से जल पहुंचने लगा है । इसमें गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब व तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर व नगर हवेली एवं दमन व दीव और पुडुचेरी इसके उदाहरण हैं ।

इस जल महोत्सव में 1862 ब्लॉक एवं 2.51 लाख ग्रामो के साथ ही 9.32 लाख विद्यालय व 9.69 लाख आंगनबाड़ी केंद्र भी जल जीवन मिशन से जुड़ चुके हैं ।

ग्राम स्तर पर जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए हर ग्राम में पांच महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो निरंतर वहां काम करेंगे । यह इस योजना का एक और अतिरिक्त महत्वपूर्ण पहलू है ।

यह भी लेकिन यह है कि देशभर के 112 आकांक्षी जिलों में 2019 में मात्र 7.69% घरों में नल से जल पहुंचता था जो जनवरी 2025 में 78.30 प्रतिशत तक पहुंच गया है । वह भी बिना किसी भेदभाव के यहां जल जीवन मिशन का काम होना ही सबका साथ व सबका विकास है । आदिवासी क्षेत्रों में धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के तहत 63,642 ग्रामों को जल जीवन मिशन में लिया गया है । इन क्षेत्र में 20 से कम परिवारों वाली बस्ती में सामुदायिक नल देने के निर्देश अतंत उपयोगी हैं । इसके लिए

50 करोड़ का बजट आवंटन भी हुआ है एवं 500 बस्तियां को प्राथमिकता पर लिया गया है । इन क्षेत्रो में कुछ अधिकारी नॉन फिजिकल कहकर इन बस्तियों पानी...

जल जीवन मिशन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित एक आंदोलन है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ माइकल क्रेमर जब भारत आए तो उन्होंने कहा भारत में हर चार मौतों में से एक मौत बच्चों में सुरक्षित जल से बचा सकते हैं

रिपोर्ट्स बताती है कि जल जीवन मिशन से बाल मृत्यु दर में कमी आई है । इससे 1,36,000 बच्चों को जीवनदान मिला है । डायरिया से होने वाली चार लाख मौतों में कमी आई है । +34 बिलियन से +101 बिलियन आर्थिक बचत हुई है और पानी लाने के उपक्रम से प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे बचे हैं । रोजगार का सृजन भी हुआ है जो तीन करोड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में आंकलित है । आज यह एक जन आंदोलन हो चुका है जो जिसमें 14000 से अधिक स्वयं सहायता समूह, समुदाय, वैज्ञानिक और NGO जुड़े हैं ।

और भी कोई उपलब्धियां है । जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की सफला स्वीकृत सैकड़ो परियोजनाओं के साथ ही साथ राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं ।

सन 1995 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने एक सपना देखा था । देश की नदियां जोड़कर देश में जल के अभाव वाले क्षेत्रो में पेयजल, सिंचाई जल की उपलब्धता और उद्योग को पानी दिलाया जा सकता है । इस सपने को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरातल पर उतारा है ।

आज 31 अतर बेसिन जल लिंक परियोजनाओं की चर्चा है । 500 वर्षों के बाद रामलला का कृत्य भव्य मंदिर बन गया है । इसमें से एक है राजस्थान की राम जल सेतु परियोजना ।

: राजस्थान के पूर्व में जाओ । आओ । हाडोती क्षेत्र में ।

नव भागीरथ नव भागीरथ गुंज है सारे प्रदेश में । ।

वीरान मरुभूमि में

सुजलाम सुफलाम सपना नेत्र में ।

नव भागीरथ नव भागीरथ गुंज है सारे प्रदेश में ।

धर्म कर्त्तव्य में समुद्र सेतु है । यह जय श्री राम लिखने पर बोलने से बजट यह ऐतिहासिक साक्ष्य है । में भी राम जी का आर्शीवाद मिल गया है । वो भी 22 जनवरी 2025 को ।

ऐसा क्यों है अध्यक्ष जी । नव भागीरथ किसे कहा जा रहा है? इस महान सदन में मुझे कहते हुए हर्ष है कि यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए कहा जा रहा है । यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के डबल इंजन की सरकार है और 30 जिलों के लिए वरदान दिया है । (17 राजस्थान + 13 मध्यप्रदेश) इसी का करिश्मा है कि आज दोनों मुख्यमंत्री और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री जी की भी राम जल सेतु परियोजना में अहम योगदान एवं भागीदारी है ।

नव भागीरथ की गुंज राजस्थान में क्यों है अध्यक्ष जी?

राम जल सेतु परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 दिसंबर 2024 को किया ।

उसे दिन अद्भुत दृश्य देखा विश्व में की मार्न प्रधानमंत्री जी पार्वती काली सिंध और चंबल का जल एक कुंभ में मिल रहे हैं एक कर रहे हैं यह डबल इंजन सरकार की ताकत है । राजस्थान में एक त्रिवेनी बनी है । मह जन कल्याण के लिए है ।

2018-2023 राज0 में सर होटलों से चली Democracy की जगह दो मोय कुर्सी से चल । वे क्या जनता की पीड़ा/किसानों की पीड़ा

यह परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश के लिए होगी । 46300 करोड रुपए खर्च होंगे । राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान पधारे थे । इससे राजस्थान के 17 जिलों के सवा तीन करोड़ से अधिक जनता को इसका लाभ होगा । उद्द्योंग, पेयजल, सिंचाई और भूजल रिचार्ज में भी इसमें अतुलनीय कार्य होंगे । अब मरुभूमि सुजलाम सुफलाम बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है । माननीय प्रधानमंत्री जी इसलिए हम नव भागीरथ हैं । माननीय जल शक्ति मंत्री जी और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जी श्री अभिनंदन के पात्र हैं ।

इस परियोजना में राजस्थान में पांच बैराज बनेंगे । अलवर व अजमेर में कृत्रिम जलाशय बनेंगे । बांध बनेंगे और बीसलपुर बांध की क्षमता 0.5 मी बढ़ेगी । साननीय मोदी जी कहा करते हैं कि हम शिलान्यास जो करते ही हैं और हम ही लोकार्पण करते हैं ।

इस योजना के तहत एमओयू और एमओए हो हो चुके हैं । और बहुत तेजी से इसमें काम हो रहा है । राजस्थान की इस राम परियोजना से काया पलट होगी । राजस्थान को 4102.60 एमसीएम पानी से उपलब्ध होगा । निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है इससे राजस्थान सुजलाम् सुजलाम् बनेगा ।

अटल जी का मेघदूत के माध्यम से संदेशः

आज राजस्थान को जनता कह रही है और "आप थे, अवाक था । हम थे आहत । आज भाजपा है, रामसेतु है । मिल रही है राहत ।

"हम स्वर्ग लोक से इस अमृत तुल्य जल को लेकर आ रहे हैं और हम इसे पर्याप्त मात्रा में ला रहे हैं । आपको हमारा संदेश यह है कि आप इसे संरक्षित करें और अगले वर्ष, जब हम फिर आएंगे तब तक के लिए इसे एकत्र करके रखिए । अगर इसे बरबाद करोगे तो तुम पर अकाल का श्राप पड़ेगा ।"

जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने राज्य की अनुसूचित क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल के लिए माही-जाबम-सोम कमला आंबी आधारित योजना बनाई है, इसमे केंद्र का सहयोग आवश्यक है । इससे लाखों लोगों को लाभ होगा । राज्य में जाखम नदी का अतिरिक्त पानी है जयसमंद झील के साथ जोड़ा जा रहा है । साथ ही साबरमती और देवास-03 और देवास-04 के कार्य भाजपा सरकार करा रही हैं । लगता है इससे इस क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल के कार्यों में तेजी से विकास होगा ।

माननीय पाटिल साहब के बारे में दो शब्द आवश्यक है वे तेजी से और जनकल्याण के बड़े निर्णय करने में विश्वास करते हैं । हमने राजस्थान के परंपरागत सिंचाई प्रणाली एवं सांस्कृतिक रक्षा के लिए बावडियो के विकास पर जब बात पाटिल साहब से की तो उन्होंने सकारात्मक टिप्पणी की है और आशा है कि जल्दी ही इस हेतु बावडियो के जीर्णोद्धार व विकास के लिए निर्...

प्रधानमंत्री जी के युगांतर कार्य निर्णय है जो पेयजल सिंचाई व उद्योग सभी की समस्या का समाधान करते हैं । इससे देश की 140 करोड़ जनता उन्हें लगातार आशीर्वाद दे रही है, आगे भी देती रहेगी । ये सभी कदम बिन पानी सब सुन' समस्या का भी समाधान है ।

माननीय मोदी जी की सरकार-

चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना

नहीं रुकना नहीं झुकना शुभंकर मंत्र है अपना ।।

के तर्ज पर पॉलिसी परालाइसिस से बाहर निकलकर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म काम कर रही है । अगर किसानों के हाथ ढीले पड़ गए तो तपस्वियों तप भी बेकार हो जाएगा ।

राजस्थान विशेषता दक्षिण राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की ओर से सरकार से आग्रह है-

राज्य का अनुसूचित क्षेत्र जो अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र है । यहां आजीविका के साधन कम है. कमजोर है । कृषि भूमि भी कम व ढलान वाली है । वहां जल संरक्षण का व्यापक कार्य किए जाए एवं प्रत्येक नदी नाले पर वाटरशेड स्ट्रक्चर बनाने की योजना लाई जाए । अनु 27 (1) से इसे जोड़ सकते है

अनुसूचित क्षेत्र में बरसों पुरानी नहरो जीर्णोद्धार के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) से केंद्र सरकार सहायता अनुदान प्रदान करें । क्षेत्र में कई परंपरागत कुंए और बावडिया हैं, को जल जीवन मिशन के साथ जोड़ा जाए

5 मीटर से अधिक ऊंचाई के पक्के बांध स्ट्रक्चर बनाने पर कथित रोक पर पुनर्विचार करते हुए इन्हें 10 मी तक किए जाने के निर्देश प्रदान किया जावे ।

क्षेत्र के खेरवाड़ा बिछीवाड़ा, कोटडा, सराडज्ञ, झाडोल, सायरा, देवला, आसपुर, धरियावद, दानपुर, कुशलगढ़, सुजानगढ़ और जल के अभाव वाला क्षेत्र है । इन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाए ।

भारत सरकार का पुनः अभिनंदन की जल जीवन मिशन की अवधि सन 2028 तक बढ़ाई । इससे पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड जैसे राज्य में जहां जेजेएम काम अत्यंत कम हुआ है । वहां पर भी मोदी जी की सरकार के द्वारा सबका साथ, सबका विकास की नीति पर काम होगा । और सुजलाम् सुफलाम् सपने के अनुरूप, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई साहब के विचार के अनुरूप, भारत की नव भागीरथ जल गंगा यात्रा पूरी होगी ।

राजस्थान में आने वाली पीढ़ी गाएगी

पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? राम सेतु परियोजना में बहे उस जैसा ।

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी): परभणी में पानी घोटाले की समस्या एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें जल आपूर्ति परियोजनाओं में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं । इस समस्या के कारण नल से जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति में बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं । पाइपलाइनों में गुणवत्ता की कमी और अनियमितताओं की खबरें आई हैं, जिससे जल वितरण में समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं ।

इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं:

जल प्रबंधन में सुधारः जल प्रबंधन में सुधार करने के लिए जल संचयन प्रणालियों का निर्माण और पाइपलाइन नेटवर्क की मरम्मत की करनी चाहिए ।

भ्रष्टाचार की जांचः जल आपूर्ति परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिए है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए है ।

जल संचयन प्रणालियों का विकासः जल संचयन प्रणालियों का विकास करने से जल की कमी की समस्या का समाधान किया जा सकता है ।

जल आपूर्ति परियोजनाओं की निगरानीः जल आपूर्ति परियोजनाओं की निगरानी करने से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है ।

जल आपूर्ति योजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण जल संकट की समस्या और बढ़ जाती है । जल आपूर्ति योजनाओं के लिए आवंटित फंड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने से जल आपूर्ति का असमान वितरण होता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या और बढ़ जाती है ।

इस समस्या का समाधान करने के लिए, हमें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाईः जल आपूर्ति योजनाओं में भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ।

जल आपूर्ति प्रणाली में सुधारः जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क और जलसंचय योजनाओं की पुनरावलोकन और गुणवत्ता जांच की जानी चाहिए ।

पारदर्शिता और निगरानीः जल आपूर्ति योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ।

स्थानीय समुदायों को जागरूक करनाः स्थानीय समुदायों को जल प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे जल संकट के समाधान में अपनी भूमिका निभा सकें ।

जल संचयन और प्रबंधनः वर्षा जल संचयन और जल प्रबंधन के तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि जल संकट को कम किया जा सके ।

मेरे परभणी जिले में भूजल स्तर में गिरावट आई है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । यह समस्या कृषि उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है । परभणी का अधिकांश क्षेत्र की जल आपूर्ति वर्षा पर निर्भर करती है, लेकिन वर्षा अनियमित होने के कारण पानी की उपलब्धता में असमानता बनी रहती है । मानसून में देरी होने पर जल संकट और भी गंभीर हो जाता है ।

जल संग्रहण और वितरण के उचित उपायों की कमी है । कई क्षेत्रों में जलसंचय प्रणाली का अभाव है, जिससे पानी का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और अपव्यय हो रहा है ।

कुछ क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है । पानी में रासायनिक और जैविक प्रदूषण होने के कारण लोगों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ता है । यहां की कृषि पानी की अत्यधिक मांग वाली होती है, लेकिन जलस्रोतों की स्थिति में सुधार नहीं होने से यह समस्या गंभीर हो जाती है ।

इस समस्या का निदान के लिए सरकार से अनुरोध है की बारिश के पानी का संचयन करने के लिए जल पुनर्भरण योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए, जैसे की जलाशयों और तालाबों की सफाई और पुनर्निर्माण, भूजल स्तर को सुधारने के लिए टैंक निर्माण, और जल पुनर्चक्रण की योजनाओं को बढ़ावा देने की जरुरत है, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों की जगह पर सटीक और आधुनिक सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग बढ़ाया जाए । स्थानीय स्तर पर लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और पानी के समुचित उपयोग की आदतें विकसित की जाएं ।

इन उपायों से परभणी संसदीय क्षेत्र में जलशक्ति समस्या को हल किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण इलाकों में पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादन में सुधार होगा ।

मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी में नल से जल (पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति) की स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, पानी की समस्या कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असंतुलित है । यहां की जल आपूर्ति प्रणाली में अनेक प्रमुख समस्याएँ और स्थितियाँ देखने को मिलती हैं:

जल संकट की समस्या वास्तव में गंभीर है । जल संकट का अर्थ है किसी क्षेत्र में उसकी खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल संसाधनों की कमी होना से है ।

परभणी संसदीय क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहां भी पानी की लगातार आपूर्ति और दबाव की कमी महसूस की जाती है । पानी की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन के कारण कई बार शहरी क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत होती है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी में "नल से जल" योजना (हर घर जल योजना) का कार्यान्वयन कुछ क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन इसका पूरा फायदा सभी ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुँच पा रहा है । कई क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्क और जल वितरण प्रणाली की स्थिति को सुधारने की जरूरत है । नल है पर जल नही इससे जनता में गलत मेसेज जा रहा है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है की नल-जल योजना का विस्तार कर परभणी संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण जिले में "नल से जल" योजना को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि हर घर तक जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, नल से जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना और नियमित निगरानी की

आवश्यकता है, ताकि प्रदूषित पानी से बचा जा सके, जल आपूर्ति प्रणाली में स्मार्ट मीटर और ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल कर पानी के वितरण की निगरानी और नियंत्रण में सुधार किया जा सकता है । पाइपलाइन नेटवर्क और जल संचयन का सही प्रबंधन करके पानी की उपलब्धता को बेहतर किया जा सकता है ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे द्वारा की गई मांगों एवं सुझावों पर सरकार ध्यान दे और मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी में नल से जल की स्थिति में सुधार करे जिससे स्थानीय

निवासियों को सुरक्षित और निरंतर पानी की आपूर्ति प्राप्त हो सके ।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : मैं जल शक्ति मंत्रालय के अधीन वित्त वर्ष 2025-26 में अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ । साथ ही, मैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्री, आदरणीय सी. आर. पाटिल जी को भी कोटि-कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ ।

"नियत साफ हो तो सपना भी सच होता है ।" हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि देश की 140 करोड़ जनता का विकास "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र पर हो । आज मैं हर्ष के साथ यह कहना चाहता हूँ कि यूपीए सरकार के शासनकाल में वित्त वर्ष 2013-14 में जल संसाधन और पेयजल के लिए मात्र 17,342 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था । लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व में, एनडीए सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में इस राशि को लगभग 6 गुना बढ़ाकर 99,503 करोड़ रुपये कर दिया है ।
मोदी जी जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं । इसलिए मैं पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ ।

यूपीए सरकार के कार्यकाल में वित्त वर्ष 2013-14 में जल संसाधन और पेयजल के लिए कुल 17,342 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे । वहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने "जल ही जीवन" को ध्यान में रखते हुए केवल पेयजल और स्वच्छता के लिए ही 74,226 करोड़ रुपये का आवंटन किया है । यह देश की 140 करोड़ जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है । इसलिए मैं पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ । "मोदी हैं तो मुमकिन है!"

समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने क्षेत्र की जनता की कुछ मांगों और समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

मेरा क्षेत्र गंगा, फुलहर, महानंदा, पुनारभवा, टंगन, श्रीमतीखाड़ी और बेहुला नदियों के किनारे स्थित है। इन नदियों में गाद जमा होने, तटों के कटाव और बाढ़ की गंभीर समस्या के कारण हर वर्ष हजारों परिवार प्रभावित होते हैं ।

विशेष रूप से, गंगा, फुलहर और कोसी नदियों के जलस्तर में अचानक भयानक वृद्धि होने के कारण रतुआ-1 एवं हरिश्चंद्रपुर 2 ब्लॉकों के सैकड़ों गाँव बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिससे हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं ।

रतुआ-1 ब्लॉक के खासमहल, नसीरुद्दीन टोला, भासाराम टोला, कान्तुटोला, महानंदा टोला और भिलाईमारी ग्राम पंचायतों के हजारों परिवार नदियों के कटाव के कारण अपना घर-बार खो चुके हैं ।

इसी प्रकार, हरिश्चंद्रपुर-2 ब्लॉक के उत्तर भगोरिया, दक्षिण भगोरिया और रसीदपुर गाँवों के 300 से अधिक परिवार फुलहर नदी के कटाव से प्रभावित हुए हैं । इन परिवारों ने अपनी जमीन, घर और रोजगार सब कुछ खो दिया है और वे सरकारी राशन पर निर्भर रहने को मजबूर हैं ।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह कटाव रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए । मगर, अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने गंगा कटावरोधी कार्यों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है । सरकार की अकुशलता और लापरवाही के कारण मेरा क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ और कटाव की गंभीर समस्या से जूझता रहता है ।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस संकट से निपटने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए और गंगा कटावरोधी कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए ।
मालदा उत्तर के कई गांवों में अभी भी पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की सुविधा सीमित है । जल जीवन मिशन के तहत ₹67,000 करोड़ के आवंटन से हम यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक घर तक "हर घर नल से जल" पहुँच सके ।

गंगा और अन्य नदियों में ट्रेजिंग कार्य को प्राथमिकता दी जाए और तटीय क्षेत्रों में जीयोबैग एवं कंक्रीट संरचना विकसित की जाए ।

मालदा क्षेत्र में गंगा और महानंदा को राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ा जाए ताकि व्यापार और यातायात को प्रोत्साहन मिले ।

मालदा उत्तर के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर गिर रहा है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अटल भूजल योजना के तहत यहाँ विशेष पैकेज प्रदान किया जाए ताकि जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें ।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँवों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए SBM-G के ₹7,192 करोड़ के बजट से मालदा उत्तर को भी एक मॉडल स्वच्छता क्षेत्र बनाया जाए ।

मालदा उत्तर की जनता को हमारी लोकप्रिय मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं । मैं फिर से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, PMKSY और अटल भूजल योजना के माध्यम से हमारे क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जाए । जय हिंद, भारत माता की जय ।

SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): I would like to express my views on the Demand for Grants for the Ministry of Jal Shakti for the financial year 2025-26. This Ministry, tasked with the crucial responsibility of water resource management, drinking water supply, and sanitation, is central to India's developmental trajectory. Yet, under this Union Government, the sector has suffered from inadequate allocations, delayed fund releases, and a step-motherly treatment towards states like Tamil Nadu, which have been at the forefront of effective water management policies.

The government of Tamil Nadu, under the leadership of our Hon'ble Chief Minister Thiru M. K. Stalin, has consistently prioritized water security, resilient water infrastructure, and sustainable management of resources. However, the Union Government's neglect in releasing the necessary funds and support has hampered the state's efforts. The data speaks for

itself. Tamil Nadu contributes significantly to the country's GDP, yet receives an inequitable share of tax devolution and centrally sponsored scheme funding. For a state that has been a leader in implementing water conservation projects, this continued discrimination is unacceptable.

The Tamil Nadu government has undertaken ambitious initiatives, including the comprehensive Tamil Nadu Water Resources Consolidation Project, which integrates surface and groundwater management to ensure year-round water availability. The Kudimaramathu scheme, an age-old participatory water conservation practice revived by the state, has rejuvenated thousands of water bodies, benefiting farmers across districts. Yet, despite repeated appeals, the Centre has failed to recognize these efforts with adequate financial support.

The allocation for the Ministry of Jal Shakti in the Union Budget 2025-26 stands at Rs 99,503 crore, only marginally higher than the previous year's allocation. However, the revised estimate for 2024-25 was a shocking 48% lower than the budgeted allocation, primarily due to drastic cuts in the Jal Jeevan Mission. The Jal Jeevan Mission, which was launched with the ambitious goal of providing tap water connections to all rural households by 2024, has not met its target. As of January 2025, only 80% of rural households have functional tap water connections, forcing an extension of the scheme to 2028. This delay, coupled with irregular fund disbursement, has particularly impacted Tamil Nadu, which has been left to manage water security with insufficient central assistance.

While Tamil Nadu has proactively pursued water conservation measures, the Centre has failed to support our demands for critical projects. The state sought enhanced financial support for the Chennai City Water Augmentation Project, which aims to ensure drinking water security for

millions. Similarly, Tamil Nadu's plea for assistance in desilting reservoirs and building additional check dams has been ignored, despite the Centre's repeated claims of prioritizing water security.

The disparity in fund allocation is evident in the Centre's refusal to provide adequate assistance under the Atal Bhujal Yojana. The scheme, meant to promote sustainable groundwater management, allocated a mere Rs 1,780 crore in 2025-26, despite growing concerns over groundwater depletion. Tamil Nadu, a water-stressed state, has been largely sidelined in this regard, with the Union Government showing greater interest in promoting projects in states governed by the ruling party at the Centre.

Moreover, the Namami Gange program, which receives significant allocations, highlights the Centre's skewed priorities. While river rejuvenation is crucial, the Union Government has completely ignored Tamil Nadu's requests for similar assistance to clean and restore the Cauvery and Vaigai rivers. This exposes the Centre's partisan approach, prioritizing projects based on political considerations rather than genuine need.

Another major concern is the implementation of the Swachh Bharat Mission-Grameen (SBM-G). The mission, crucial for rural sanitation, has received stagnant funding, with Rs 7,192 crore allocated for 2025-26, the same as the previous year. Tamil Nadu has made remarkable strides in rural sanitation, yet it faces bureaucratic hurdles in receiving central funds. The delay in fund transfers has affected the timely completion of solid and liquid waste management projects in rural Tamil Nadu.

The financial discrimination extends beyond project-specific allocations. Tamil Nadu's overall share in tax devolution has steadily declined. In January 2025. the Centre allocated Rs 1,73,030 crore as tax devolution

to all states, yet Tamil Nadu received only Rs 7,057.89 crore, a mere 4.08% share despite contributing nearly 9% to the national GDP. Over the past three decades, this unjust tax distribution policy has cost Tamil Nadu an estimated Rs 3.57 lakh crore in lost revenue. This systemic bias is reflected in water sector allocations as well. where Tamil Nadu receives disproportionately low funding despite its pressing needs.
Even in disaster response, Tamil Nadu has been neglected. Despite suffering recurrent floods and cyclones, the state has struggled to receive its due share from the National Disaster Response Fund. The financial assistance requested for Cyclone Fengal, which devastated 14 districts, was grossly inadequate. Water infrastructure restoration after such calamities requires immediate central assistance, yet Tamil Nadu has been left to fend for itself.

This Union Government's step-motherly treatment of Tamil Nadu must end. The people of Tamil Nadu demand their rightful share of resources and recognition of the state's pioneering efforts in water management. The Centre must immediately release pending funds for the Jal Jeevan Mission, increase allocations under Atal Bhujal Yojana, and ensure equitable distribution of disaster relief funds. It must also acknowledge Tamil Nadu's proposals for new water conservation projects and river rejuvenation initiatives.

Our Hon'ble Chief Minister Thiru M. K. Stalin has repeatedly emphasized the importance of cooperative federalism, where states are treated as equal partners in national development. However, this government continues to centralize decision-making and deny states their rightful financial dues. We will not remain silent as Tamil Nadu is deprived of its fair share.

I urge the Union Government to rise above partisan politics and allocate resources based on genuine need. Water security is not a luxury it is a fundamental right of every citizen. The people of Tamil Nadu will not tolerate continued neglect. It is time for the Centre to fulfill its constitutional obligations and ensure just and equitable water governance across all states.

Thank you.

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) : मैं एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला, एक बेटी, और उस गांव की मां की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ ? जो आज भी 2025 में 'हर घर जल' के उस वादे को पूरा होते देखने के लिए आस लगाए बैठी है ।

सरकार ने वादा किया था कि 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचेगा ।

आज 2025 है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लड़कियाँ स्कूल छोड़कर, माएं रसोई छोड़कर, 2 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी ला रही हैं ।

सरकार कहती है कि 13 करोड़ घरों को जल कनेक्शन मिल गया । लेकिन CAG की 2023 रिपोर्ट बताती है कि पानी की गुणवत्ता, नियमितता, और सप्लाई ढांचा सब काग़ज़ों पर ही हैं ।

कहीं टंकियाँ सूखी, कहीं पाइपें टूटी, और कहीं पानी की टेस्टिंग किट्स को तालों में बंद कर दिया गया है जैसे किसी संग्रहालय की चीज़ हों ।

सरकार को पाइपलाइन की बहुत चिंता है, लेकिन असल में जो सबसे तेज़ी से बह रहा है- वो है भ्रष्टाचार ।

राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ठेके मनचाहे ठेकेदारों को, बिना पारदर्शिता, बाँटे गए ।

CAG ने बताया कि 80% जल सैंपल कभी टेस्ट ही नहीं हुए - जबकि उन्हें 'कवर्ड' घोषित कर दिया गया ।

काग़ज़ों में पानी है, ज़मीन पर प्यासी जनता है ।

अब बात करते हैं नमामि गंगे मिशन की - ₹22,000 करोड़ खर्च हो गए ।

संसद की समिति कहती है- सिर्फ 36% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही काम कर रहे हैं ।

और गंगा माता, जिनकी सफाई का दावा किया गया, आज भी दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल हैं ।

ये कोई योजना नहीं, ये सिर्फ़ फोटो खिंचवाने की एक स्कीम बनकर रह गई है ।

सरकार बताती है - सब कुछ बेहतर हो गया है ।

लेकिन मैं पूछना चाहती हूं:

जब किसान खेत सूखा छोड़कर पलायन कर रहे हैं,

जब टैंकर माफिया खुलेआम धंधा कर रहे हैं,

जब महिलाएं दिन का आधा हिस्सा पानी के लिए निकाल देती हैं,

तो किस दुनिया की प्रगति की बात हो रही है?

क्या सरकार ने कभी जल ऑडिट अथॉरिटी बनाई ? नहीं! क्या किसी ठेकेदार को सज़ा मिली जिसने प्रोजेक्ट लटकाया? नहीं!

लेकिन फोटो खिंचवाने की स्पीड देखिए- उसमें कोई देरी नहीं ।

पानी कोई 'पी.आर. इवेंट' नहीं है । पानी, जीवन है ।

आज गांवों में एक और नई चुनौती सिर उठा रही है ? जल चोरी और पाइपलाइन को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना ।

मिर्जापुर ज़िले में उदाहरण सामने आया है, जहां नई पाइपलाइन डाले जाने के कुछ ही दिनों बाद,स्थानीय आपसी रंजिशों और राजनीति के चलते उन पाइपों को तोड़ दिया गया ।

नतीजा ?

गांव फिर से प्यासा, और करोड़ों की लागत धूल में मिल गई ।

मैं पूछना चाहती हूँ -

क्या सरकार ने ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में पाइपलाइन सुरक्षा या निगरानी की कोई व्यवस्था की है?

या सिर्फ आंकड़ों की घोषणा करना ही इनकी प्राथमिकता है?

While the world prepares for water scarcity and climate crisis, this government seems busy building castles in the sand.

No long-term aquifer recharge plan

No clear groundwater extraction policy enforcement

And despite NITI Aayog warning that 21 cities will run out of groundwater, no urgency, no vision.

Sir, even basic rainwater harvesting rules are not followed in government buildings.

मैं एक महिला हूं । मैं जानती हूं कि पानी की एक-एक बूंद की क्या कीमत होती है । जब पानी नहीं होता, तो रसोई की आग ठंडी होती है । बच्चों के

स्कूल छूटते हैं । खेत बंजर हो जाते हैं ।

इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर नहीं, हक़ से कहती हूं:

वेंट मैनेजमेंट बंद कीजिए, जल प्रबंधन शुरू कीजिए । झूठे आंकड़ों से जनता को भ्रमित मत कीजिए ? सच्चाई को स्वीकार कीजिए ।

SHRI AVIMANYU SETHI (BHADRAK): Request for Permanent Flood Prevention Measures in Bhadrak District caused by the overflowing of the River Baitarani : I hope this letter finds you well. I am writing to bring to your attention the severe and recurring issue of annual flooding in the Bhadrak district, caused by the overflowing of the River Baitarani. This

persistent problem has been devastating our farmlands and homes, significantly affecting the lives and livelihoods of our people.

Every year, the floodwaters of the River Baitarani inundate vast areas, leading to extensive damage to agricultural lands and residential properties. The recurrent nature of these floods is a major concern for our constituents, who face immense hardships and financial losses as a result. There is an urgent need for a permanent solution to mitigate this issue and protect our people from future flooding.

I kindly request your immediate intervention to implement effective flood prevention measures in the Bhadrak District. Possible solutions could include the construction of embankments, levees, and retention basins, as well as the improvement of river channelisation and the implementation of advanced early warning systems. Additionally, floodplain zoning and land use planning could help in minimising the impact of floods on our farmlands and residential areas.

Your prompt action in addressing this critical issue will be greatly appreciated by the people of our constituency. They have been enduring the devastating effects of floods for far too long and are in dire need of a sustainable and permanent solution.

I look forward to your favourable response and swift action.

श्री छोटेलाल(रॉबर्ट्सगंज) : हमारी संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र में सिंचाई के आभाव मे आज तक क्षेत्र के किसान परेशान रहते है ।

समाजवादी पार्टी की सरकार में सिंचाई परियोजना बनाया गया था मगर न हर-नाली न बनने से दुद्धि विधानसभा के किसान आजतक बाट जोह रहे है ।

बाणसागर परियोजना का पानी अहिरौरा बांध में गिराकर वहां से भोका कट बँधी में पानी लाया जाए ताकि चकिया विधानसभा के किसानों का भलाई हो सके ।

नगवा बांध से छोटा नाव के जरिए लिफ्ट से करहि बंधी, देवरी बँधी, बलियारी बंधी में पानी दिया जाए व देशवली परियोजना से छोटा लिफ्ट से किसानों को पानी दिया जाए ।

स्पेन लिफ्ट जहां पानी नहर में आता है, बांध से छोटा लिफ्ट बनाकर भेलाही बँधी में छोड़कर कई बँधी से होते पूरे घोरावल विधानसभा के किसान लाभान्वित होंगे ।नगवा बोध के पानी बजरिया नहर सफाई कराकर नौगढ़, चकिया तक पानी जाएगा । आज तक किसान परेशान है, मगर समुचित क्षेत्र को पानी नहीं मिल रहा है ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र समाधान करने का कृपा करें ।

SHRI EATALA RAJENDER (MALKAJGIRI): I would like to express my views on the Demands for Grants for the Ministry of Jal Shakti.

With rapid urban expansion, State Governments are struggling to provide sufficient infrastructure and services to meet the needs of growing populations. It is commendable that the Central Government has recognized this challenge and allocated thousands of crores of rupees under the Smart Cities Mission and AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) for the sanitation and for the facilitation of reliable and safe drinking water and also other infrastructure.

In the same spirit, I would like to bring to your attention the urgent development needs of my parliamentary constituency i.e. Malkajgiri, one of the largest and fastest-growing cities in Telangana. This constituency has become a major urban hub where people from different cities and States migrate in search of livelihood. This diverse and rapidly growing population has placed immense pressure on the existing infrastructure, making it difficult for local authorities to meet the rising demands. Therefore, I urge the Ministry to allocate special funds for the sanitation projects and for the facilitation of drinking water.

I wish to bring to your kind attention the ecological crisis faced by Hyderabad due to the contamination of its lakes with sewage water. Once, this city was known as City of Lakes. Its water bodies, including the iconic Hussain Sagar, have become severely polluted due to unchecked drainage inflows. This has further led to the pollution that has destroyed aquatic ecosystems, killing fish and other biodiversity. The seepage of contaminated water is leading to groundwater pollution and toxicity. Polluted lakes contribute to waterborne diseases and air pollution due to toxic gases.

To restore the ecological health of these lakes, I urge the Hon'ble Minister of Jal Shakti to allocate sufficient funds for the diversion of sewage water from these lakes and for the development of alternative sewage treatment infrastructure and also some immediate alternatives such as strengthening Sewage Treatment Plants (STPs) to ensure that only treated water enters the lakes. There is also need for diversion of untreated drainage away from the lakes through modern sewage management systems.

I would also like to draw your kind attention towards the severe pollution crisis affecting the Musi River in Hyderabad, which has become heavily contaminated due to unchecked industrial effluents and chemical waste. The river, once a lifeline for the region, now poses serious environmental and health risks due to toxic discharges and untreated sewage inflows. The deterioration of Musi's surroundings has led to severe water pollution, making the river unfit for any use. Groundwater contamination is also threatening drinking water sources. It has also led to public health hazards, as the toxic air and waterborne diseases affect residents.

I request the Ministry to allocate sufficient funds and take immediate action for enhancing and upgrading Sewage Treatment Plants (STPs) along the river to ensure proper treatment of wastewater before discharge. Measures are needed to be taken for strict monitoring and regulation of industrial waste disposal to prevent hazardous effluents from entering the river.

A clean and rejuvenated Musi River is essential for environmental sustainability, groundwater recharge, and the overall well-being of Hyderabad's residents. Therefore, I once again urge you to take swift action and prioritize this matter for the allocation of necessary funds.

With rapid urbanization, many newly formed colonies and bastis are facing severe drinking water shortages due to a lack of proper infrastructure. As populations grow, the demand for clean and safe water is increasing, but inadequate supply and pollution of groundwater have left thousands struggling for this basic necessity.

Since the Central Government has been actively supporting water infrastructure projects, I humbly request financial assistance for Telangana to ensure access to clean drinking water for all.

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): I support demand for grants for 2025-26 for Jul Shakti ministry.

This ministry is in it's infant stage in a way that it was structured only in 2019 & present dynamic & dedicated minister Shree C.R. Patil Ji is only second minister in the history. The has done remarkable job which the country has noted in very short span of time.

The task of water management resources is duel & shared between the center & the state. It is very truly said that next world war could be fought on water. But congress never understood importance of water & like all

other initiatives, it is Modi ji who formed new ministry of Jal Shakti. The ministry ensures adequate availability for diverse needs of water such as drinking, domestic, sanitation, irrigation & industrial.

Water scarcity is to pause greatest challenge in future on account of increased demand coupled with shrinking supplies due to over utilization & pollution. Water is a cyclic resource with abundant supplies on the globe. Approximately 71% of the earth's surface is covered with water but freshwater constitutes about only 3% of total water supply on the earth, a very small portion is effectively available for human use & it varies with space & time. The world has witnessed many tensions & disputes on sharing & control of this scarce resource, we too have witnessed in our country across among communities, regions & states.

The ministry is comprising of mainly The Department of Water Resources, River Department & Ganga Rejuvenation & the Department of Drinking Water & Sanitation for which record breaking Rs 99503 cr. combined has been allocated in this budget. Under the guidance, motivation & supervision by hon. Modi saheb **"Jal hai to Jivan hai"**, the department initiated two centrally sponsored schemes:

The Jal Jeevan Mission (JJM) started way back in 2019 has been allocated massive Rs 67000 crore in this budget. JJM ensured good water quality supply to all 19 crores households & public institutions of which 15 crores households have functional household tap water connections (FHTCS). As on February 2024, over 14.24 crore (73.93%) rural households have tap water at their doorsteps. After a village achieves 100% functional tap water connections, the gram panchayat formally certifies the village as **"Har Ghar Jal",**

Second scheme is Swachh Bharat Mission Grameen (SBM-G) has been allocated Rs. 7192 crores in this budget. All villages were declared ODF

in 2019 under phase 1 of the scheme. Under phase II, out of 5.86 lakh villages covered under ODF Plus villages, 5.63 lakh villages (96%) are declared ODF Plus villages. Similarly, The Department of water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (DOWR), looking after water resource management, flood & irrigation management, ground water management & rivers rejuvenation, has been allocated Rs. 25277 crores in this budget. The department monitors river inter linking project & PM Krishi Sinchai Yojana (PMSKY) which was launched in 2015-16 to increase cultivable area under irrigation, improve water availability to farms & increase water use efficiency, PMSKY has been allocated Rs. 8260 crores for 2025-26 which implements two schemes-

The Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) which takes up medium irrigation projects.

Har Khet Ko Pani (HKKP) takes up minor irrigation projects.

India accounts for about 2.45 percent of the world's surface area, 4 percent of the world's water resources & 17 percent of the world's population. Total water available from precipitation in the country in a year is barely 4000 cubic km from surface & replenishable ground water is 1869 cubic km. Out of this only 60 percent is of beneficial use. So, it comes to about total only 1122 cubic km.

There are four major sources of water i.e. rivers, lakes, ponds & tanks. We have about 10360 rivers & their tributaries longer than 1-6 km each. India has last coastline due to which number of lagoons & ponds are formed. Similarly, there are four types of natural freshwater sources: surface water, subterranean river flow, ground water & frozen water. Oceans are the largest source of water on earth holding about 96.5 all the planet's water.

India has been water stressed since 2011. Per capita projected water availability in India in cubic meters was 1820 in 2001, 1651 in 2011, 1486 in 2021, 1367 in 2031, 1282 in 2041 & 1228 in 2051. 61% of utilizable water is from surface water sources & 39% from ground water where the government has done commendable job by making thousands of borewell throughout the country. 90% of water is used for agriculture, 7% domestic use & 2% for industrial use. I fully appreciate the hard work put in & the new direction that hon. minister Shree CR Patil ji has given to his ministry under the able leadership of Modi ji particularly in exploiting, strengthening & generating new storage capacity of underground water in the country during 2024-25. These efforts will go long way in future to generate new capacity of water supply for future generation in the country. I fully end endorse & support demand for grant for 2025-26 for Jal Shakti ministry.

Pani re Pani Tera Rang Kaisa, Jis me Mila do Lage us Jaisa

जल शक्ति मंत्री (श्री सी. आर. पाटिल): माननीय सभापति जी, मेरे सभी साथियों ने जल संबंधी विभागों के बारे में बजट में चर्चा के दौरान जिस तरह से अपनी बात रखी है, जो स्वयं में दर्शाता है कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में जल और स्वच्छता को कितना महत्व दिया गया है । मैं सभी साथियों और सांसदों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए वे गहन विचार कर रहे हैं और चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जल से जुड़े विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों को एकत्रित करके महत्वपूर्ण क्षेत्र को समग्र रूप से देखने का दृष्टिकोण विकसित किया गया है ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2019 में पानी से संबंधित बिखरे हुए विभिन्न विभागों और योजनाओं जैसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग को मिलाकर जलशक्ति मंत्रालय की स्थापना की । माननीय प्रधान मंत्री जी ने केवल जलशक्ति मंत्रालय की स्थापना करके पानी को अहमियत नहीं दी

बल्कि इस क्षेत्र में निरंतर निवेश और पर्याप्त सरकारी फंडिंग सुनिश्चित करके पूरी तरह से समर्थन भी दिया है ।

महोदया, आपने देखा होगा कि वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक बजट में उस समय की सरकार ने दस सालों में सिर्फ 1,02,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था । माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2014 से 2024 तक 4 लाख 29 हजार 173 करोड़ रुपये आबंटित किए । इससे यही पता चलता है कि चार गुना ज्यादा पैसा देकर इस काम को कितनी अहमियत दी गई है ।

महोदया, भारतीय संविधान के अनुसार जल राज्यों का विषय होने के बावजूद भारत सरकार स्वतंत्र रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में राज्यों की क्षमता विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता तथा ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है । वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जलशक्ति मंत्रालय को 99,502 करोड़ रुपये आबंटित किए गए । जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को 25,276 करोड़ रुपये और पेयजल और स्वच्छता विभाग को 75,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं ।

12.38 hrs *(Hon.Speaker in the Chair)*

मैं आज पेयजल और स्वच्छता विभाग की कुछ प्रमुख योजनाओं और बजटीय प्रस्तावों का संक्षेप में वर्णन करना चाहता हूं । ?जल जीवन मिशन? में 15 अगस्त, 2019 को नल जल कनैक्शन 3.23 करोड़ थे यानी सिर्फ तीन करोड़ के आसपास कनैक्शन थे जो कि उस समय टोटल कनैक्शन्स के 17 परसेंट थे । 13 मार्च, 2025 तक कुल 15.52 करोड़ घरों में नल जल कनैक्शन्स दिए गए जो कि आज की तारीख में सभी कनैक्शन्स का 80 परसेंट है । जेजेएम का अनुमानित परिव्यय 3.60 करोड़ रुपये रखा गया था । केंद्र के हिस्से से 2.7 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए और वर्ष 2025-26 के बजट में 67 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए गए । जल जीवन मिशन की शुरूआत में प्रयोगशालाओं की संख्या सीमित थी और अब तक 2182 से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं । इसके अलावा लगभग पांच लाख गांवों में 25 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग देकर पानी का सैम्पल चैक करने के किट दी गई है ताकि वे अपने घर और गांव में जो पानी आ रहा है, जो पानी बच्चे पी रहे हैं, वह किस क्वालिटी का है, उसे चैक कर सकें ।

यह ट्रेनिंग सरकार ने इसलिए भी दी है कि सरकार को विश्वास है कि नल से जल योजना में जो पानी जाएगा, वह शुद्ध पानी होगा और किसी के मन में शंका नहीं होनी चाहिए । आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने महिलाओं को महत्व देते हुए उनको पहली बार इसके अंदर जोड़ा है ।

वर्ष 2019 में 14 हजार 20 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां थीं । अभी 14 हजार में से सिर्फ 314 बस्तियां रह गई हैं । इसके अंदर भी बहुत बड़ा काम माननीय प्रधान मंत्री मोदी साहब ने किया है । वर्ष 2019 में 7 हजार 996 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां थीं । अभी सिर्फ 251 बस्तियां रह गई हैं । इसके अंदर भी बहुत बड़ा काम हुआ है । आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण मानव शरीर के अंदर जो नुकसान होता था, हम उस नुकसान से लोगों को बचा पाये हैं । शेष प्रभावित 314 और 251 बस्तियों में भी सामुदायिक जल शोधन संसाधनों से जल की आपूर्ति की गई है । आज किसी भी मानव शरीर में इस तरह का पानी नहीं जा रहा है । माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में यह काम किया है ।

नोबल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर के अध्ययन के अनुसार सुरक्षित पेयजल की 100 परसेंट पहुंच सुनिश्चित होने से प्रतिवर्ष 1 लाख 36 हजार बच्चे, जो 5 साल से कम आयु के हैं, उनको मौत से बचाया जा सकता है । डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि सुरक्षित पेयजल की 100 परसेंट पहुंच सुनिश्चित होने पर 4 लाख लोगों को डायरिया से होने वाली मौतों से बचा पायेंगे । उसके अंदर यह भी बहुत बड़ा काम हुआ है और करीब 8.5 लाख करोड़ रुपये की बचत भी इसके कारण होने वाली है । नल से जल योजना के अंतर्गत शुद्ध जल देने के जो परिणाम हैं, वह इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं । डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार पानी की 100 परसेंट पहुंच से महिलाओं के 5.5 करोड़ घंटों का समय भी बचा है । महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है कि उसके घर में आने वाला पानी सुरक्षित है या नहीं, वह चैक कर रही हैं और अपने गांव का पानी भी चैक कर रही हैं । महिलाओं को कई किलोमीटर तक जाना पड़ता था और घंटों तक बोझ उठा कर आना पड़ता था । डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के साढ़े 5 करोड़ घंटे बच रहे हैं । महिलाएं अपना समय अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए और आपने आर्थिक उपार्जन में खर्च कर रही है । उनको बोझा उठाने से भी मुक्ति मिली है ।

निर्माण चरण के दौरान 59.9 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की भी क्षमता इसके अंदर हुई है । आईआईएम बैंगलोर और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट के अनुसार मिशन के संचालन और रख-रखाव में 11.18 लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना इसके अंदर बनी है । स्वच्छ भारत मिशन ? ग्रामीण भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया । यह एक व्यापक अभियान है । मिशन के पहले चरण में 2 अक्टूबर, 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया । यह कोई सरकार ने घोषित नहीं किया बल्कि सभी गांवों ने, सभी राज्यों ने अपने आपको शौच मुक्त घोषित किया है । वर्ष 2014 से 11.83 करोड़ शौचालय बनाये गये, करीब 12 करोड़ शौचालय बनाये गये । इन शौचालयों की वजह से पूरे देश के अंदर करीब 60 करोड़ लोग, जो बाहर शौच के लिए जाते थे, उनकी आदत में बदलाव आया है । यह क्रांतिकारी कदम हमारे देश में स्वच्छता मिशन के कारण आया है । इसके लिए भी मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

डब्ल्यूएचओ के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2014 से 2019 के बीच में 3 लाख जिंदगियां बची हैं, जल से अलग बची हैं और स्वच्छता के कारण 3 लाख जिंदगियां बची हैं । यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार 50 हजार रुपये प्रति परिवार की वार्षिक बचत भी हुई है । वर्ष 2024 में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका ?नेचर? में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार प्रतिवर्ष 60 से 70 हजार बच्चों की जिंदगियां बचाई गई हैं ।

यह रिपोर्ट अलग-अलग स्वतंत्र संस्थाओं की है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया । यह मोदी सरकार की रिपोर्ट नहीं है । इसलिए स्वच्छता पर आप कोई बात नहीं कर सकते हैं ।

स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के द्वितीय चरण को 1 अप्रैल, 2020 से लागू किया गया । इसका लक्ष्य सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाना था और सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कवर करना था । इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना है कि शौचालय तक हर घर की पहुंच हो और शौचालय साफ-सुथरा दिखना चाहिए । ओडीएफ प्लस गांवों में शौचालय तक हर घर की पहुंच के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है । ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों के लिए गांवों में शौचालय तक हर घर की पहुंच के साथ सॉलिड वेस्ट

मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ दृष्टिगत स्वच्छता भी सुनिश्चित की जाती है । आज की तिथि में 5 लाख 64 हजार गांवों में ओडीएफ प्लस टॉयलेट्स बने हुए हैं और 4 लाख 44 हजार गांवों में ओडीएफ प्लस मॉडल के शौचालय बने हुए हैं । वर्ष 2025-26 के बजट में, लगभग 7 हजार करोड़ रुपए थे । इसके चरण-एक में, वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक कुछ आवंटन 71 हजार करोड़ रुपए था । इसके चरण-दो में, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक कुल आवंटन 31 हजार करोड़ रुपए था ।

इसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ के तहत गोवर्धन योजना लागू की गई, जो स्वच्छता, ऊर्जा, जैविक खाद और सतत कृषि को बढ़ावा देते हुए किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन प्रदान करती है ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह योजना विशेष रूप से, डेयरी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है । सीबीजी संयंत्रों के माध्यम से, गोबर को स्वच्छ ऊर्जा में बदला जा रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ती है और इससे पारम्परिक ईंधनों का निर्माण भी घट रहा है । वर्तमान में, 145 वाणिज्यिक सीबीजी संयंत्र कार्यरत हैं, जिनसे 850 मिट्रिक टन बायो गैस प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है । इससे 800 सामुदायिक बायो गैस संयंत्र संचालित हो रहे हैं, जिनसे प्रतिदिन 39,000 घनमीटर बायो गैस का उत्पादन हो रहा है । इस योजना ने गुजरात में सहकारी आन्दोलन को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

राज्य की प्रमुख दुग्ध सहकारी समितियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके 20 से अधिक सीबीजी संयंत्र और 30 हजार से अधिक व्यक्तिगत बायो गैस ईकाइयों की स्थापना का संकल्प लिया गया है । ?सरकार के साथ सहकार? के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की जनभागीदारी के साथ काम करने की जो इच्छा है, वह इसके अन्दर आपको दिख रही है और उसके परिणाम भी यहाँ पर दिख रहे हैं ।

अब मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण से संबंधित विभागों की प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बजट के प्रस्तावों पर भी आपसे चर्चा करूँगा ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । इस योजना का

उद्देश्य बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके सिंचाई क्षमता को बढ़ाना है ।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2016 से एआईबीपी परियोजनाओं को कुल 18 हजार करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है । इसके साथ ही, राज्य के हिस्से में, नाबार्ड के द्वारा 34,432 करोड़ रुपए का ऋण राज्यों को मुहैया कराया गया है, जिसके लिए केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों को लगभग 2,900 करोड़ रुपए का इंट्रेस्ट सबवेन्शन भी दिया गया है । अब तक कुल 63 बड़ी योजनाएं और मध्यम योजनाएं पूरी की गई हैं ।

26.27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता विकसित की गई है ।

माननीय अध्यक्ष जी, कमांड और क्षेत्र विकास जल प्रबंधन योजना ? कमांड क्षेत्र विकास में वर्ष 2025-26 के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है । इस योजना के उद्देश्य सिंचाई क्षमता के उपयोग को बढ़ाना तथा सहभागी सिंचाई प्रबंधन को भी बढ़ावा देना है । अप्रैल, 2016 से इस योजना के अंतर्गत कुल 3,129 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता इसमें जारी की गई है ।

माननीय अध्यक्ष जी, हर खेत को पानी ? इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 1,100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और नाना मंत्री जी ने किया है । सतही लद्युु सिंचाई एवं जल निकायों की मरम्मत, पुनर्जीवन और पुनर्स्थापन, ट्रिपल-आर योजनाओं का उद्देश्य छोटी परियोजनाओं के द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाना है । अप्रैल, 2016 से इस योजना के अंतर्गत कुल रुपए 5,541 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है तथा 4.5 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास इसके अंदर किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष जी, केन-बेतवा लिंक परियोजना ? केन-बेतवा नदी लिंकिंग परियोजना से 10.62 लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए इसके अंतर्गत पानी मिलेगा । 62 लाख लोगों को इसके अंदर पीने का पानी मिलने वाला है । इसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिसंबर, 2021 को 44,605 करोड़ रुपए की लागत पर मंजूरी दी है । अब तक इस योजना पर 10,723 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है । महत्व की बात यह है कि दौधन बांध का निर्माण कार्य भी ढाई सालों

से शुरू हो गया है । मोदी जी के काम की रफ्तार इसके अंदर दिखती है । कल हमारे एक साथी सांसद पूछ रहे थे कि पता नहीं यह कब शुरू होगा, कब पूरा होगा । यह मोदी सरकार है, हम समय से काम शुरू करते हैं और समय से पहले ही उसे पूरा कर देते हैं । ? (व्यवधान) वर्ष 2030 तक यह योजना खत्म हो जाएगी । वर्ष 2025-26 के लिए भी 2,400 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी नैशनल रिवर कन्ज़र्वेशन प्लान ? गंगा के अलावा अन्य नदियों के संरक्षण हेतु यह योजना राज्यों, केन्द्रीय शासित प्रदेशों के प्रयासों को समर्थन देती है । 2,941 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स विकसित किए गए हैं । वर्ष 2025-26 के लिए 558.09 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है । बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम में भी वर्ष 2025-26 के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । यह योजना बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी कार्यों, जल संसाधान परियोजनाओं की जांच तथा बांग्लादेश, भूटान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ बाढ़ प्रबंधन एवं सहयोग हेतु सहायता प्रदान करती है ।

माननीय अध्यक्ष जी, पोलावरम सिंचाई योजना वर्ष 1907 से विलंबित थी । कई सालों तक अलग-अलग सरकारें रहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहब ने वर्ष 2015 में करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा देकर वह काम शुरू करवाया है । ? (व्यवधान) इस साल भी करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा देकर वर्ष 2026 तक काम पूरा करने हेतु उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी सूचित किया है और उनको पैसा भी दे रहे हैं ।

85 सालों से विलंबित इस योजना के बारे में न कभी किसी ने कुछ किया, न किसी ने कुछ बोला । यह जो काम बाकी थी, उसे भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहब कर रहे हैं । इसके अलावा अगस्त, 2024 में कैबिनेट ने प्री योजनाओं को 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए 5,512 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता अभी तक उनको दे दी गई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025-26 में इन राष्ट्रीय परियोजनओं के लिए 5,936 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया है । यह बताता है कि समय पर योजना पूरे करने के लिए धन भी आबंटित किया जाता है । इस परियोजना से 2.91 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी । विशाखापट्टनम के लिए 23.44 टीएमसी

जल आपूर्ति की जाएगी । 540 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएग, जिससे 28.5 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा, यानी इसके अंदर बहुत बड़ा काम चल रहा है और सबको इसका लाभ होने वाला है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की कुछ प्रमुख केन्द्रीय और क्षेत्रीय योजनाओं के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा ।

नमामि गंगे मिशन के लिए भी 3,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । फरवरी, 2025 तक 6,335 एमएलडी क्षमता वाली 206 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । इनमें से 3,600 और 3,446 एमएलडी क्षमता वाली 127 परियोजनाएँ पूरी हो गई हैं, जिनकी स्वीकृत लागत 16,821 करोड़ रुपये है । जबकि अन्य परियोजनाओं के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 21,531 करोड़ रुपये खर्च भी हुए हैं । स्वीकृत 5,158 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क में से 4,543 किलोमीटर का कार्य भी पूरा हो गया है और बाकी कार्य भी बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है । जल गुणवत्ता में सुधार आया है । पिछले कुछ वर्षों में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, जो निरन्तर प्रयासों का परिणाम है । उत्तराखंड में वर्ष 2015 में नदी की धारा बीओडी 5 एमजी थी, लेकिन वर्ष 2022 तक यह अप्रदूषित श्रेणी बीओडी वन में आ गई है । पाँच से बीओडी एक पर आ गया है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 में गंगा की धारा बीओडी 15 एमजी थी, जो वर्ष 2022 तक सुधार के बाद बोओडी एक पर आ गई है । यह बहुत बड़ा काम इसके अंदर हुआ है । इसी तरह वर्ष 2015 में बिहार में गंगा की धारा बीओडी 25 एमजी थी, लेकिन वर्ष 2022 तक इसमें सुधार के साथ अब यह बीओडी एक श्रेणी में आ गई है । बिहार में बीओडी एक पर आना बहुत बड़ी बात है । पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2018 में गंगा की धारा बीओडी 15 थी, वह भी बीओडी 8 पर आयी है । उसमें अभी और कमी लाने की कोशिश जारी है । संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से गंगा नदी के पुनर्जीवन में नमामि गंगे कार्यक्रम की उल्लेखनीय सफलता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है । दिसंबर, 2022 में संयुक्त राष्ट्र परिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक ने इसे दुनिया की शीर्ष दस पुनर्स्थापन प्रमुख पहलों में शामिल किया है । मोदी है तो मुमकिन है ।? (व्यवधान) गंगा नदी में सुधार का प्रभाव क्या होता है, जो गंगा पहले मैली थी, आज गंगा में सुधार आने के कारण आप देख सकते हैं कि जो डॉल्फिन गंदे पानी में नहीं जी सकती, गंगा परिस्थितिकी तंत्र में सुधार को गंगा में डॉल्फिन की बढ़ती संख्या ने प्रमाणित किया है ।

वन्य जीवन संस्थान के वर्ष 2018 के आधारभूत आंकड़ों का वर्तमान अध्ययन से तुलना करने पर गंगा में डॉल्फिन की जनसंख्या 3,330 प्लस से बढ़कर 3,926 हो गई है । अब गंगा नदी के उन हिस्सों में डॉल्फिन की उपस्थिति दर्ज की गई है, जहाँ पहले उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं थी, जैसे बिठूर में प्रयागराज के बीच का हिस्सा । इसके अलावा बाबई और बागमती नदियों में भी पहली बार डॉल्फिन देखी गई है । अटल भूजल योजना में भी इस योजना के लिए 1,780 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है ।

13.00 hrs

अध्यक्ष जी, 150 जिले डार्क जोन घोषित हैं । कई ब्लॉक्स में भी डार्क जोन्स हैं । इस वजह से वहां बोर नहीं किया जा सकता है, कुएं बनाए नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऐसा करना प्रतिबंधित है । वहां के किसान बिना पानी अपने खेत में फसल नहीं उगा सकते हैं । माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने अटल भू-जल योजना द्वारा पहले ही कदम में 80 जिलों को लेकर काम शुरू किया । इस साल एक साथ 150 जिलों में काम शुरू हो गया है । हमारा टार्गेट है कि आने वाले एक साल के समय में पूरे देश में एक भी जिला डार्क जोन नहीं रहना चाहिए । इसके लिए हम आपसे भी मदद मांग रहे हैं । इस योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों के लिए जल सुरक्षा योजनाएं सामुदायिक परामर्श से तैयार अद्यतन की गई हैं । 6.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल दक्ष कृषि पद्धतियों के अंतर्गत लाया गया है । 61 ब्लाक्स और 1333 पंचायतों में भू-जल की स्थिति में सुधार दर्ज हुआ है ।

माननीय अध्यक्ष जी, कई योजनाएं भू-जल के बेहतर प्रबंधन और शासन हेतु चलाई जा रही हैं । जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंपिंग कार्यक्रम भी शामिल है । इस योजना के लिए 509 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ प्रावधान प्रस्तावित किया गया है । नदी बेसिन प्रबंधन योजना के अंदर भी उत्तर-पूर्वी राज्यों के मास्टर प्लान के संरक्षण, जांच, अद्यतन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव की रोकथाम कार्य को सुगम बनाने के लिए 243 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया है ।

अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जल मिशन के लिए मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जल शक्ति अभियान के कैच दि रेन कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश हो रही है । माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने मार्च,

2021 में कैच दि रेन कार्यक्रम के लिए एक योजना बनाई थी । 6 सितम्बर, 2024 को सूरत के एक कार्यक्रम में जब मोदी जी वर्चुअल जुड़े थे, तब उन्होंने कहा था जल संचय, जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए । उन्होंने इसके साथ यह भी कहा था कि कर्म भूमि से मातृ भूमि के लिए सभी लोगों को कोई न कोई योगदान देना चाहिए । उन्होंने वहां शब्द प्रयोग किए थे कि ?कर्म भूमि से मातृ भूमि? उन्होंने ?जन्म भूमि? के लिए नहीं कहा, क्योंकि लोगों की दृष्टि में ?जन्म भूमि? वह स्थान होगा, जहां उन्होंने जन्म लिया है । इस वजह से उन्होंने ?मातृ भूमि? शब्द का प्रयोग किया था । मोदी साहब के आह्वान के ऊपर आपने देखा होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी जो सूरत के प्रवासी और व्यापारी थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम शुरू किया है । अलग-अलग राज्यों में एनजीओज के साथ मिलकर पांच महीने के अंदर जो रिस्पाँस मिला है, वह भी देखने योग्य है । 8.30 लाख जल संचय के लिए जो स्ट्रक्चर बने हैं, वे पानी निकालने के लिए नहीं, बल्कि जमीन में पानी उतारने के लिए बने हैं । मोदी साहब जैसा कहते हैं कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में यूज होना चाहिए । हमारे यहां करीब 4 हजार बीसीएम बारिश होती है । हमारी आवश्यकता 11 हजार बीसीएम की है और वर्ष 2050 तक हमारी आवश्यकता 1180 बिलियन बीसीएम की हो जाएगी । आज हमारे पास जो संसाधन है, जिनके द्वारा हम जल संचय कर सकते हैं, वह सिर्फ 750 बिलियन बीसीएम हैं । हमारे पास इतने बड़े-बड़े डैम हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 250 बिलियन बीसीएम है । हमें जागना पड़ेगा और हमें कुछ करना पड़ेगा । इसीलिए दूरदर्शिता के साथ माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को जागृत करते हुए और उनका सहयोग मांगते हुए जमीन के अंदर पानी उतारकर गांव का पानी गांव को मिले, खेत का पानी खेत को मिले, इसके लिए जो योजना बनाई है, उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं । हमारा टार्गेट 31 मई तक 10 लाख स्ट्रक्चर्स का था लेकिन हम इस समय सीमा में 10 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना लेंगे और आगे भी यह कार्यक्रम जारी रखेंगे । हमें विश्वास है कि आप सभी का भी इसमें सहयोग रहेगा । मैं गुजरात के सभी एमपीज का भी आभार व्यक्त करूंगा कि किसी ने 50 लाख रुपये, किसी ने एक करोड़ रुपया जल संचय के लिए दिए । उन्होंने कलेक्टर और डीडीओ को यह पैसा अपनी ग्रांट में से दिया है और इस राशि से काम हो रहा है । मैं सभी सांसदों से भी विनती करूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र में जल संचय के लिए अपनी ग्रांट में से कुछ हिस्सा उपयोग करें ।

इस पहल में समुदाय की भागीदारी, संयुक्त वित्तपोषण और उद्योगों के सीएसआर फंड्स का भी उपयोग हो रहा है । व्यक्तिगत दाताओं एवं परोपकारी लोगों के सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है । इस योजना के वास्तविक निगरानी हेतु जे.एस.जे.बी. मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें 17 मार्च, 2025 तक 8.30 लाख कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचनाओं को जोड़ा गया है ।

महोदय, किसी के पास इसके बारे में प्रश्न हो सकता है, पर कई लोगों को तो प्रश्न खड़ा करने की आदत ही होती है, इसलिए हमने पहले से इस योजना में जो बोर या स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं और वे जहां खड़े होते हैं, उस गांव का नाम, उस गली का नाम, उसकी तारीख, किसने उसमें योगदान दिया, कितना फीट वह बोर हुआ है, उस स्ट्रक्चर के फोटो को, उसकी लोकेशन के साथ हम कलक्टर के माध्यम से वेबसाइट पर डालते हैं । हमने उसका एक्सेस सिर्फ कलक्टर को दिया है कि सिर्फ कलक्टर ही उसे वेरिफाई करते हुए उसे वेबसाइट पर अपलोड कर सके । मोदी जी के आह्वान पर लोगों ने इसका समर्थन करते हुए इसमें जो अपना सहयोग दिया है, उन सभी लोगों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, बालू साहब ने कहा कि वर्ष 2014 के चुनाव में चुनाव अभियान के दौरान मोदी जी ने अन्तरराज्यीय नदियों को जोड़ने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात कही थी । कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं । मैं बिल्कुल कम समय में उनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा । टी.आर. बालू साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ?मैं मोदी जी के विरुद्ध नहीं हूं ।? यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वे भी यह स्वीकार करते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ।

महोदय, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 30 नदी जोड़ परियोजनाओं की पहचान की है, जिनमें 16 प्रायद्वीपीय और 14 हिमालयी घटक शामिल हैं । उन्होंने हिमालयी नदी के बारे में भी कहा था । अब तक 11 लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) और 26 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफ.आर.) तैयार की जा चुकी है । जल, राज्य का विषय होने की वज़ह से अब तक सभी बेसिन राज्यों की सहमति न होने के कारण अभी यह काम रुका हुआ है । पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है । हमें विश्वास है

कि बहुत जल्दी वे राज्य भी इसकी सहमति देंगे और नदी जोड़ो का कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा ।

आपने देखा होगा कि अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच भी पी.के.सी. योजना थी । वह कई सालों से लम्बित थी । माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने उसमें हस्तक्षेप किया । दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री और सरकार की ओर से इसकी सहमति मिली और करीब 70,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिवर लिंकिंग का यह काम आगे बढ़ने जा रहा है ।? (व्यवधान) भारत की नदियां, विशेष रूप से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी को भी जोड़ा जाना चाहिए, उन्होंने इसके लिए भी कहा है । प्रधान मंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 221 किलोमीटर की दूरी को जोड़ने के लिए केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की पहल की है ।

उन्होंने यह भी कहा कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं, हालांकि, अधिक पहल करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था । मैं उनकी बातों का स्वागत करता हूं और उनके प्रति बहुत-बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं । गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी लिंक योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है । राज्यों के साथ सहमति बनाने की प्रक्रिया चल रही है । भारत सरकार इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता पर रखते हुए जल्द ही संबंधित राज्यों से परामर्श करते हुए इस पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी ।

यू.पी. और मध्य प्रदेश के बीच केन-बेतवा परियोजना के बाद अब तक 9,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया गया है । अब तक इस लिंक योजना में 10,723 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

महोदय, मैं एन.के. प्रेमचन्द्रन जी की बात भी करूंगा । क्या प्रेमचन्द्रन जी उपस्थित है?? (व्यवधान) हमारे माननीय सदस्य उपस्थित है । प्रेमचन्द्रन जी, आपका आभार भी है । आपने एक बात कही कि आप पांच साल जल मंत्री रहे हैं । आपको अफसोस है कि आप कुछ कर नहीं पाए । मुझे भी अफसोस है कि आप जैसा आदमी इतने अनुभवी है, लेकिन काम नहीं कर पाए । उसका अफसोस भी है । मगर जब मेरा कार्यकाल पूरा होगा, तब मैं अफोसस व्यक्त नहीं करूंगा । यह मैं आपसे कह सकता हूं । आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया, आपने बुक बनाया, आपने लॉ बनाया । आपने पेपर पर बहुत सारा

काम कर लिया, परंतु पानी तो जमीन पर चाहिए । हमारे घर में पानी चाहिए । आपने एक बात यह भी कही कि नल से जल योजना संभव ही नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने यहां तक कह डाला कि यह योजना संभव ही नहीं है । आज जब हमारे यहां 15 करोड़ घरों में नल से जल जा रहा है, तब यह संभव नहीं है, ऐसा बात करना ठीक नहीं है । आज 80 परसेंट लोगों के घर में पानी जा रहा है । वहां शुद्ध जल जा रहा है । उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं । मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से देखिए । अगर आपके मन में कोई गलतफहमी या अविश्वास है तो आप मुझसे जरूर मिले । मैं आपके साथ बैठ कर बात करूंगा । मैं आपका सलाह भी लूंगा । जहां भी रुकावटें आई होंगी, उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे । आपका पांच साल का अनुभव और अभ्यास हमें जरूर काम देगा । ऐसा मुझे पूरा विश्वास है ।

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि इसमें पैसा ही नहीं देना चाहिए । अभी 80 परसेंट लोगों को कनेक्शन मिला है । अभी हमें चार करोड़ और घरों में पानी देना है । 20 परसेंट काम बाकी है । अगर हम उनको फंड नहीं देते हैं तो कैसे काम पूरा होगा । मोदी साहब ने इस योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया है । इस योजना के लिए 67,000 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया गया है । इसका महत्व है और आवश्यकता भी है । उन्होंने सीएजी रिपोर्ट की बात भी कही थी । मंत्रालय का स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया, ऐसा भी उन्होंने कहा था । उन्होंने ऑडिट पैरा पढ़ने के बाद कहा कि मैं अभी उसको नहीं पढ़ूंगा । मैं उनसे कहना चाहूंगा कि राज्य द्वारा अपनी हिस्सेदारी न देने की समस्या के कारण जो पैसा हम खर्च नहीं कर पाए हैं, ऑडिट पैरा उसके ऊपर है । यह केंद्र के ऊपर नहीं है । इसीलिए, शायद आपने उसको टाल दिया होगा । राज्य द्वारा अपनी जिम्मेदारी न दिए जाने की वजह से भारत सरकार अपनी हिस्सा नहीं दे पाई है । केंद्र या किसी भी केंद्र शासित योजनाओं की गाइडलाइन की तरह पहले राज्यों को ही अपना हिस्सा खर्च करना अनिवार्य होता है । उसी के पश्चात भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है । माननीय सांसद जी ने जिस रिपोर्ट की बात कही है । उसमें राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है । केंद्र सरकार हर तरीके से राज्य सरकार को मदद करती है और आगे भी करती रहेगी ।

महोदय, माननीय सदस्य जब मंत्री थे, उस समय की उन्होंने केरल की बात कही थी । मैंने इसे यहां पर लिखा है । उन्होंने कहा था कि संरक्षित पेयजल प्राप्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है । यह अधिकार तो पहले से ही है । मगर आज तक किसी ने इस बारे में काम नहीं किया, यह भी आपको कहना चाहिए था । इतनी सरकारें आईं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया । पहली बार मोदी सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है । राज्य की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी आप जल उपलब्धता की बात कर रहे हैं । उसे धोखाधड़ी में पिछले 70 सालों में दिखाया गया कि एक हैंडपंप लगा है, जिससे पूरे गांव को पानी मिल जाएगा । एक हैंडपंप लगाने से पूरे गांव को पानी मिल जाएगा, अगर ऐसा किसी सरकार की सोच है तो वह बहुत सीमित सोच थी । आज किसी भी गांव में हैंडपंप नहीं चल रहा है । यह उसी समय बंद हो गया था । आज घरों में सीधे नल से जल आ रहा है

महोदय, जल जीवन मिशन एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन गया, ऐसा भी उन्होंने कहा है । यह सही बात है । 45 सौ करोड़ रुपये का बकाया पहले से ही है, यह बात भी सही है । इसी के लिए बकाया होगा कि राज्यों ने अपना हिस्सा नहीं दिया होगा । अगर आप अपना हिस्सा देते हैं तो आपको फंड जरूर मिल जाएगा । कई शिकायत भी आई हैं । कई सांसदों ने भी शिकायत की हैं । पहले स्टेट की जवाबदारी के कारण उनको 50 परसेंट या उससे ज्यादा की सहायता करते थे । राज्य सरकार टेंडर करती है । राज्य सरकार टेंडर के बारे में तय करती है । काम कराने की जवाबदारी राज्य सरकार की है । अगर उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ गड़बड़ी होती हैं, तो राज्य सरकार की जवाबदारी है । उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं था । हमें कोई भी कंप्लेंट मिलती है, मुझे कई सांसदों ने लिख कर दिया है । हमने अपनी टीम को फील्ड में भेज कर उसको वेरिफाई करके राज्य सरकार को भी बताया है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए । वहां क्या-क्या एक्शन हुआ है, वह भी मैं आपको जरूर बता देता हूं ।

दो सौ पृष्ठीय रिपोर्ट में उसका उल्लेख तक नहीं किया है । राहुल कस्वां जी, मैंने सुना था कि आदमी की जब आयु बढ़ती है तो उसके चश्मे का नम्बर आता है और आयु ज्यादा बढ़ती है तो चश्मे का नम्बर बदलता रहता है । आप सामने क्या चले गए, आपकी दृष्टि बदल गई । दस सालों तक आपने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है । एक साल में आप दूसरी बात कर रहे हैं ।?(व्यवधान) राहुल जी, यह ठीक नहीं है । ?(व्यवधान) मैं राहुल जी से बात कर रहा हूं । ?(व्यवधान) राहुल कस्वां जी ने राजस्थान फीडर द्वारा

राजस्थान, विशेषकर चुरू में सिंचाई के संबंध में प्रश्न उठाया । राजस्थान फीडर की स्थिति बहुत खराब थी, ऐसा भी उन्होंने कहा । यह सही बात है । उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए भी कहा । उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए । भूमिगत पाइप लाइनों के माध्यम से पानी देने के निर्माण कार्य में जो गड़बड़ी है, उन्होंने उसके बारे में भी कहा । मैं उनको यही कहना चाहूंगा, जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें पूरी जवाबदारी राज्य सरकार की है, राज्य सरकार टेंडर करती है, राज्य सरकार ही टेंडर का काम देती है । उसका जो डीपीआर बनता है, उसके मुताबिक हम आर्थिक या टेक्निकल सहयोग करते हैं ।?(व्यवधान) माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम कोई भी गड़बड़ी चलने देने वाले नहीं हैं । अगर कोई गड़बड़ी पहले भी हुई होगी, तो उसका भी हम जवाब लेंगे । किसी भी गड़बड़ी करने वाले को नहीं छोड़ेंगे । मैं सभी सांसदों को कहता हूं कि किसी भी पार्टी का हो, किसी भी स्टेट का हो, आप हमें लिखकर दे दीजिए ।?(व्यवधान) अगर आपमें लिखने की हिम्मत न हो तो आप हमें फोन से बता दीजिए, मिलकर बता दीजिए । हम उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे । यह लोगों का अधिकार है । ?(व्यवधान) उन्हें पानी मिलना चाहिए और उन्हें पानी मिलेगा ।?(व्यवधान) मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं ।?(व्यवधान) हम सभी योजनाओं की जांच कर लेंगे, आप चिन्ता मत कीजिए ।

मोहम्मद जावेद, हमारे सांसद मित्र ने किसी रिपोर्ट के बारे में बताते हुए कहा कि 122 देशों के इंडेक्स के अंदर हमारा देश 120वें नंबर पर है । पानी महत्वपूर्ण है, तभी उन्होंने कहा । यह जो रिपोर्ट है, वह बहुत पुरानी है । उन्होंने जब की बात कही है, उसके बाद बहुत सी नदियों में पानी आ गया, पानी का स्तर सुधर गया । माननीय सांसद द्वारा प्रस्तुत चिंता में जल गुणवत्ता सूचकांक, वाटर क्वॉलिटी इंडेक्स में भारत के 120वें स्थान पर होने का उल्लेख किया गया । उपरोक्त रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में जारी की गई थी, जो कि दरअसल वाटर ऐड की रिपोर्ट पर आधारित थी । यह रिपोर्ट वर्ष 2019 के जेजेएम के पहले की स्थिति पर थी । जेजेएम वर्ष 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया । वर्ष 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने यह बात कही थी । इसका मतलब कांग्रेस के सांसद महोदय ने सही कहा कि 70 वर्षों की कांग्रेस सरकार के बाद 120 वें नंबर पर भारत का वाटर इंडेक्स था । आज की तिथि में 80 प्रतिशत से अधिक परिवारों को साफ पीने का पानी मिल रहा है । इसकी वजह से भारत की रैंकिंग

में बहुत बड़ा सुधार आया है । अभी कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है, नहीं तो उसकी बात मैं जरूर आपके सामने रखता ।

वर्ष 2022 में यूएन की स्वतंत्र संस्था द्वारा एसडीजीज़ लक्ष्यों की मॉनीटरिंग रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के घरों में साफ पानी की उपलब्धता की स्थिति 66 पर्सेंट बताई गई । वर्ष 2024 के अंदर यह स्थिति सुधरकर 78 पर्सेंट हो गई । इस समय यह महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष 2019 में आर्सेनिक प्रभावित रिहाइशों की जो संख्या 14 हजार थी, वह वर्ष 2025 में सिर्फ 314 हो गई । इसी तरह फ्लोराइड रिहाइशों की संख्या 7,996 थी, वह घटकर 255 रह गई है ।

शेष प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से उनको जो पीने का पानी कम मिलता है, उनको पीने के लिए पानी दिया जाता है, उनको आर्सेनिक और फ्लोराइड का पानी नहीं पीना पड़ता है । सनातन पाण्डेय जी ने अपनी बात रखी थी, उन्होंने कई मुद्दे उठाए ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आज की स्थिति के अनुसार 15.53 यानी 80 परसेंट ग्रामीण स्तर पर पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है । जल जीवन मिशन के तहत परियोजना से संबंधित 80 परसेंट काम हो चुका है । मैं इसको रिपीट नहीं करके आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा । इस संबंध में कुल 12 राज्यों में कार्रवाई हुई । जहां गड़बड़ी हुई, उसकी बात भी आप सुन लीजिए । हमने जब इस पर काम करना शुरू किया, आपकी ओर से जो भी कम्पलेंट्स आईं, जो फोटोग्राफ्स आए, सही कम्पलेंट थी, कई जगहों पर गड़बड़ी हुई । चाहे भाजपा शासित राज्य हो या अन्य पार्टी शासित राज्य हो, हमने किसी को छोड़ा नहीं है । बारह राज्यों में कार्रवाई हुई, जिसमें 21 विभागीय अधिकारी, 20 कार्यपालक अभियंता निलंबित किए गए । 256 अधिकारियों पर जांच बैठाई गई,1436 एजेंसियों को प्रतिबंधित करके दंडित किया गया, दो ठेकेदार प्रतिबंधित हुए, 26,455 विभागीय कार्रवाई की गई है । उसके अतिरिक्ति भी जल जीवन मिशन की प्राथमिकता आधारित क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक कर रही है । मिशन के त्वरित क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल जीवन मिशन टीम द्वारा मैदानी दौरा भी हो रहा है ।

आपने भी संगम में स्नान किया होगा, गंगा नदी में स्नान करने के लिए सभी लोग गए थे, आप भी गए होंगे । गंगा नदी में बेतवा, यमुना और काली नदी मिलती हैं । यदि यमुना

नदी दिल्ली में स्वच्छ नहीं है तो जल प्रयागराज में कैसे स्वच्छ हो गया, आप मानते हैं कि यमुना दिल्ली में स्वच्छ नहीं है । राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा पानी को ट्रीट किया गया, सबके सहयोग से किया गया, प्रयागराज में पानी स्वच्छ हो गया, महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने स्नान किया । माननीय मोदी जी को बहुत-बहुत अभिनंदन ।

आपके टाइम में गंगा में पानी स्वच्छ नहीं था, यह हम मानते हैं । हमारे मित्र हनुमान बेनीवाल जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए । उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये का बजट खर्च होने के बावजूद नदियों में प्रदूषण नहीं रुका है । मैंने अभी कहा कि नदियों की स्थिति बेहतर हुई है और बेहतर करने की हमारी पूरी कोशिश है । आपका सभी का सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल हो जाएगा । ये हमारी देश की नदियां हैं, हम सबको मिलकर उसे साफ करना है । मोदी सरकार आर्थिक सहयोग कर रही है, हम सभी मिलकर उसको करेंगे । जल जीवन मिशन योजना की धीमी प्रगति के बारे में कई सांसदों ने कहा, पुष्पेंद्र सरोज, सनातन पाण्डेय, श्री एंटो एन्टोनी, एडवोकेट फ्रांसिस जॉर्ज, श्री वीरेन्द्र सिंह, उम्मेदा राम और प्रतिमा मण्डल जी ने जल जीवन मिशन के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठाए थे । जब 80 करोड़ घरों में कनेक्शन देना है तो छोटी-मोटी कम्पलेंट्स तो आएंगी । हमारी कोशिश रहेगी कि कोई कम्पलेंट न आए, कम्पलेंट आएगी तो उसके ऊपर एक्शन होगा । ? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं । उनकी बातों को स्वीकार कर रहा हूं, जो भी गड़बड़ी या कमियां रही होंगी, उसको भी जल्द से कम्पलीट करने वाले हैं ।

भ्रष्टाचार और अनियमितता के बारे में भी कई सांसदों ने कम्प्लेन किया है । उनमें श्री निलेश ज्ञानदेव लंके, श्री राहुल कस्वां, श्री सुदामा प्रसाद, श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे, श्री चंदन चौहान और श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे शामिल हैं । उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई हैं । अगर हम इसकी बात करें तो मैंने पहले ही बताया है कि यह राज्यों की जवाबदेही है । इसको राज्य को करना है और राज्य ही इसको कर रहे हैं । ? (व्यवधान)

***m25 माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपको क्या प्रॉब्लम है? माननीय मंत्री जी, ने स्पष्ट रूप से सारी बातों को बताया है और आपकी एक-एक बातों के बारे में क्लेरिफिकेशन दिया है । उन्होंने कहा है कि किसी भी राज्य में किसी भी तरह की

अनियमितता होगी तो वे उसकी जांच कराएंगे । आप कह रहे हैं कि मंत्री जी बहुत बढ़िया हैं । आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री सी. आर. पाटिल: महोदय, वर्ष 2024-25 में जेजेएम फंड का उपयोग कम हुआ है, ऐसा भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है । जो फंड की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 में लगभग 22,964 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और लगभग पूरी राशि का उपयोग हो चुका है । मिशन के लिए प्रारंभिक अनुमानित कुल बजट 3.60 लाख करोड़ रुपये था । वह अनुमानित बजट था । उस समय डीपीआर नहीं बने थे । जब मोदी जी ने योजना बनाई थी, उस समय कितना होगा, क्या होगा, वह कैसे पता चल सकता था । आप योजना की साइज देखिए । इसके अंदर 84 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी । इसको हम पीएम गति शक्ति योजना के तहत चला रहे हैं । कल तक 14 लाख किलोमीटर पाइपलाइन की डिजाइन गति शक्ति योजना में आ गई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है । पीएम गति शक्ति योजना में पाइपलाइन का डिटेल आने से क्या होगा? अगर किसी को रोड तोड़ना होगा या कोई डेवलपमेंट का काम करना होगा तो वहां के इंजीनियर को, वहां की सरकार को, वहां के कलेक्टर को और वहां के अधिकारियों को पता होगा कि यहां से लाइन जा रही है और इसका नुकसान नहीं होना चाहिए । आप लोगों ने भी कहा कि कई जगह पर लाइन टूटी हुई है । आप सोचिए कि पूरे विश्व में आज तक इतनी बड़ी योजना नहीं बनी है । 15 करोड़ लोगों के घरों में नल जा रहा है । 84 लाख किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जा रही है । मोदी जी ने यह जो किया है, वर्ल्ड में कभी किसी देश की सरकार ने इतना बड़ा नहीं किया है और न कर पाएगी । यह भी मैं आपको बता सकता हूं ।

मिशन के लिए अनुमानित कुल बजट जो 3.60 लाख करोड़ रुपये था, उसमें केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये था, जो हंड्रेड परसेंट यूटिलाइज हो गया है । जल राज्य का विषय है । योजना के डिजाइन में क्या गड़बड़ी हुई और उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए योजनाओं की डिजाइन, प्लानिंग, स्वीकृति और क्रियान्वयन राज्यों की जिम्मेदारी है । कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पूरी राशि उपयोग हो चुकी है । राज्यों ने बड़ी-बड़ी डिजाइन बनाई थीं । उनको लगा कि पहली बार केंद्र सरकार की ओर से मोदी साहब पैसा दे रहे हैं तो हम बड़ी डिजाइन बना लेते हैं । उन्होंने

पहले की अनुमानित डिजाइन से बड़ी डिजाइन बना ली । उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च, 2024 तक जो भी डीपीआर आए थे, जो भी मंत्रालय में स्वीकृत किए गए हैं, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए इस साल भी 67,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । माननीय वित्त मंत्री जी ने भी वर्ष 2028 तक इस योजना को पूरा करने के लिए यहां पर अपने वक्तव्य में विश्वास दिलाया है ।

पीएम मोदी जी के, ?No one should be left behind? मंत्र के अनुसार उनके मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में ?जल जीवन मिशन? को वर्ष 2028 तक पूरा करने के लिए कुल बजट को बढ़ाने की घोषणा कर दी है ।

जेजेएम के भ्रष्टाचार के बारे में जो बात हुई है, हमने उसके बारे में कहा है कि गड़बड़ी हुई होगी । हम उसको चेक भी कर रहे हैं और आपसे भी सहयोग मांग रहे हैं । हम सब मिलकर काम करेंगे । मैं बताऊंगा कि क्या कार्रवाई हुई है, जो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी । छत्तीसगढ़ में छः कार्यपालक अभियंता निलंबित किए गए हैं । किसी माननीय सदस्य ने छत्तीसगढ़ का प्रश्न उठाया था । 109 अधिकारियों, 13 एजेन्सियों और एक टीपीआई पर कार्रवाई हुई है । उत्तर प्रदेश में 10 अधिकारी निलंबित किए गए हैं । 115 पर अनुशासनात्मक जांच, 48 एजेन्सियों, 114 टीपीआई सदस्यों और 10 फर्मों पर भी कार्रवाई हुई है ।

गुजरात में एक विभागीय अधिकारी और सात संविदा अधिकारी निलंबित किए गए हैं । 111 एजेन्सियां प्रतिबंधित की गई हैं और उनकी जांच जारी है । बिहार में 26,455 विभागीय कार्रवाई हुई है, 32 एजेन्सियों पर दंड और 612 मामले जांचाधीन हैं । पश्चिम बंगाल में सभी मामलों की जांच चल रही है । अभी तक 1,225 एजेन्सियों पर कार्रवाई हुई है । तमिलनाडु में 544 शिकायतें दर्ज हुई हैं और 532 मामलों में कार्रवाई पूरी हुई है ।

झारखंड में चार कार्यपालक अभियंता निलंबित हुए हैं, दो ठेकेदार प्रतिबंधित और सात मामलों पर जांच जारी है । राजस्थान कार्यकारी आदेश रद्द तथा गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जयपुर में शिकायत दर्ज कर दी गई है । हरियाणा में चार शिकायतों पर जांच चल रही है और एक मामले की रिपोर्ट सौंपी गई है । उत्तराखंड में तीन मामलों की जांच और दो सतत मामलों पर प्रक्रिया जारी है । केरल में 13 मामलों की जांच जारी

है और दो में विभागीय कार्रवाई हुई है । हिमाचल प्रदेश में दो मामलों की जांच और एक मामले में कार्रवाई हुई है ।

जेजेएम के तहत परियोजनाओं में ठेकेदारों के चयन और भुगतान की प्रक्रिया तथा हमने प्रशासनिक कार्य संबंधित राज्यों से इसके ऊपर आग्रह किया है कि इसको साथ में जोड़िए तथा जल्दी से इसके ऊपर काम करना चाहिए । मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं । जल संरक्षण और सफाई अपने आपमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है । कई लोगों ने कहा है - श्री राजकुमार चाहर, श्री सनातन पांडेय, एडवोकेट चन्द्र शेखर, श्रमती प्रतिमा मण्डल, श्री राजाभाऊ वाजे, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री बापी हलदर, श्री पप्पू यादव, श्री धैर्यशील माणे जी ने गंगा तथा अन्य नदियों की सफाई पर प्रश्न उठाया था । इन लोगों ने यमुना, गोदावारी, इन्द्राणी तथा अन्य नदियों में बढ़ती प्रदूषण की समस्या पर चिंता जताई थी ।

हम लोग कह सकते हैं कि ?नमामि गंगे कार्यक्रम? के तहत परियोजनाओं को पूरा करने की कोशिश चल रही है । ?नमामि गंगे कार्यक्रम? में प्रदूषण नियंत्रण पर महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है । 3,446 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता विकसित की गई है । पिछले 10 सालों में यानी वर्ष 2014 से पहले की क्षमता से 30 गुना अधिक क्षमता बढ़ाई गई है । 127 परियोजनाएं और 152 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) सात-आठ वर्षों में पूरे किए गए हैं । वर्ष 2014 से पहले के तीन दशकों की प्रगति की तुलना में वर्तमान प्रगति कई गुना अधिक है ।

मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि 100 कैपेक्स और 15 ओपेक्स हो सकता है, जिसमें निर्माण अवधि दो वर्ष होती है । दो वर्ष के दौरान केवल 40 प्रतिशत कैपेक्स का भुगतान ब्याजधारी को किया जाता है । जो लोग कहते हैं कि इतना पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ है, जब किसी को टेंडर देते हैं, तो काम करने के बाद ओएंडएम में भी उसका पैसा देना होता है । 15 साल तक और उसके काम के आधार पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार उसको दिया जाता है । जो पूरा पैसा आवंटित किया गया है, अगर उसको दे देंगे, तो वह काम नहीं करेगा । इससे काम की मॉनिटरिंग भी होती है । उसके कारण जल की जो समस्या है, उसका शुद्धिकरण भी होता है । अगर आप टेंडर की कंडीशन देखेंगे, तो कैपिटल के साथ उसमें 100 प्रतिशत पैसा खर्च हो रहा है ।

अभी-अभी पप्पू यादव जी ने जो पत्र भेजा है, उसका भी जवाब दे दिया है । श्री राहुल कस्वां तथा श्री एंटो एन्टोनी इत्यादि सदस्यों ने योजना के क्रियान्वयन में सांसदों की उचित भूमिका के बारे में बात की है । यह विषय आपके महत्व का है ।

जल जीवन मिशन में माननीय संसद सदस्य के कार्यक्षेत्र की योजनाओं की निगरानी हेतु दिनांक 29 जनवरी, 2021, 03 अगस्त, 2021, 27.10.2021 और 20.12.2021 को भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को सूचित किया गया है कि आप उसके बारे में पूछ सकते हैं और यह आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है । ?जल जीवन मिशन? योजना के लिए दिशा मीटिंग में माननीय संसद सदस्य को स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाना पड़ेगा और आपको डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान में बुलाना पड़ेगा । दिशा कमेटी, जिसकी अध्यक्षता माननीय संसद सदस्य करते हैं, उसकी नियमित बैठक में भी जल जीवन मिशन की समीक्षा आप कर सकते हैं । मिशन द्वारा चल रही योजनाओं के भूमि पूजन तथा उद्घाटन के समय में भी आपको कंपल्सरी आमंत्रित किया जाना चाहिए । यह भी सूचना सभी राज्यों के कलेक्टर्स को दी गई है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं 16 साल से इस सदन में हूं । पहली बार मुझे इतना लंबा बोलने का मौका मिला है । मुझे बहुत कम डिस्टर्बेंस के साथ आप सबने सुना है और मुझे सहन किया है, मैं इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । जो जल संचय जन भागीदारी, जन आंदोलन में परिवर्तित करना है, मैं उसमें भी आप सबका सहयोग चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : आप और भी कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री सी. आर. पाटिल : मैं बजट अनुमोदन के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री सुधाकर सिंह, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या बोलना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir.

I fully agree with the hon. Minister. Yes, it is absolutely the dream of the hon. Prime Minister ? Har Ghar Jal, that is, Jal Jeevan Mission. It is the flagship programme of the NDA Government, led by Shri Narendra Modi. We fully appreciate it. We are all supporting it. Let the dream of the Prime Minister be fulfilled.

There is a specific question. It is not only on my part but almost all the Members from the Opposition have criticized it that so many misappropriations are going on as far as the Jal Jeevan Mission is concerned. The hon. Minister has said that the implementing authority is the State. But in such a case, can the Government of India evade their responsibility? They are saying that the implementing authority is the State Governments, so it is absolutely the responsibility of the State Governments; we are not responsible. You are responsible to the Parliament because for the year 2024-25, we have given you more than Rs. 70,000 crore. You have only spent Rs. 22,000 crore. Then what is the purpose?

My point is this. What is the purpose for which the Demand is being granted? I would like to ask whether the Government of India under the leadership of the hon. Prime Minister ? since it is the dream of the hon. Prime Minister, he has repeated several times ? will conduct a social audit throughout the country, thereby exposing the reality of the scheme. That has to be done. That is the point which I would like to make.

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री सुधाकर सिंह, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, प्रो. वर्षा एकनाथ गाड़कवाड़, श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री राजकुमार रोट, श्री मनीश तिवारी और श्री राजीव राय ने जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे ।

अब मैं उन सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के सामने मतदान हेतू रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्षः अब मैं जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है : -

?कि कार्य-सूची के दूसरे स्तंभ में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63 के सामने प्रविष्ट मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान पर किए जाने वाले खर्चों को चुकाने के निमित्त, आवश्यक धनराशियों को पूरा करने के लिए, संबंधित धनराशियां, जो कार्य-सूची के तीसरे स्तंभ में दिखाई गई राजस्व रेखा और पूंजी लेखा की रकमों से अधिक न हों, भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को प्रदान की जाएं ।?

DEMAND FOR GRANTS OF UNION BUDGET FOR 2025-2026 VOTED BY LOK SABHA.

No. and Title of the Demand	Amount of Demands for Grants voted by the House	
1	2	
61-Ministry of Information and Broadcasting	Revenue Rs.	Capital Rs.
Ministry of Jal Shakti 62-Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation 63-Department	32607,40,00,000	558,50,00,000

of Drinking Water and Sanitation	74224,82,00,000	1,20,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

13.41hrs